mediaauditornews@gmail.com Epaperdainikmediaauditor.in वर्ष-02 अंक-83 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

मनेन्द्रगढ़
26 मार्च 2026 गुरुवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

मनेन्द्रगढ़, रीवा एवं सतना से एक साथ प्रकाशित

म.प्र. के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लगी भीड़

गाड़ियों की टंकियां फुल कराने पहुंचे लोग, धक्का-मुक्की; पुलिस तैनात करनी पड़ी

भोपाल, एजेंसी। मध्यप्रदेश के इंदौर, उज्जैन, नीमच, झाबुआ, आगर मालवा, शाजापुर और अन्य शहरों में मंगलवार शाम पेट्रोल पंपों पर अचानक भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ईजराइल-ईरान युद्ध के बीच पेट्रोल खत्म होने और कीमतें बढ़ने की अफवाह फैलने पर लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने पहुंचे।

लोगों की भीड़ इतनी बढ़ी कि कई पंपों पर धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। प्रशासन और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल अधिकृत स्रोतों से जानकारी लें।'

वहीं पेट्रोलियम कंपनियों ने भी कहा कि 'देशभर में ईंधन की कोई कमी नहीं है। अफवाहों पर ध्यान न दें और सामान्य रूप से ही ईंधन लें।'

गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू, विधानसभा से पास हुआ यूसीसी बिल 2026

अहमदाबाद, एजेंसी। गुजरात में एक बड़ा कानूनी और राजनीतिक फैसला सामने आया है, जहां विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल 2026 को पास कर दिया है। इस कदम के साथ ही गुजरात, उत्तराखंड के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है, जिसने समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। यह फैसला राज्य में कानून व्यवस्था और सामाजिक ढांचे को एक समान नियमों में बांधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

विधानसभा में यह बिल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा पेश किया गया था, जिसे चर्चा के बाद पास कर दिया गया। इस कानून के तहत शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान नियम लागू होंगे। हालांकि अनुसूचित जनजातियों और कुछ विशेष समुदायों को इस कानून से बाहर रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे समाज में समानता और पारदर्शिता बढ़ेगी।

क्या है यूसीसी बिल और इसमें क्या बदलाव होंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 का उद्देश्य अलग-अलग धर्मों के निजी कानूनों को खत्म कर एक समान कानूनी ढांचा बनाना है। इस बिल में शादी और तलाक के नियमों को एक जैसा किया गया है। साथ ही लिव-इन रिलेशनशिप को भी कानूनी मान्यता देते हुए उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है।

इसके अलावा लिव-इन संबंध खत्म करने के लिए भी औपचारिक प्रक्रिया तय की गई है।

शादी और परिवार कानून में क्या नए नियम लागू होंगे? इस बिल के तहत बहुविवाह पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति तभी शादी कर सकता है जब उसका जीवनसाथी जीवित न हो। यानी एक समय में केवल एक ही शादी को मान्यता मिलेगी। इसके अलावा उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े मामलों में भी समान नियम लागू होंगे, जिससे विवाद कम होने की उम्मीद है।

किन लोगों पर लागू नहीं होगा यह कानून? सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कानून पूरे गुजरात में लागू होगा और राज्य के बाहर रहने वाले गुजरात के निवासियों पर भी लागू रहेगा। लेकिन अनुसूचित जनजातियों और कुछ पारंपरिक अधिकार वाले समुदायों को इससे बाहर रखा गया है। संविधान के तहत संरक्षित इन समूहों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यह छूट दी गई है।

चुनाव आयोग बोला: बंगाल की वोटर लिस्ट में डिस्प्ले एरर ठीक हुआ

एक दिन पहले सभी वोटर्स 'जांच' के दायरे में बताए गए; टीएमसी बोली थी- क्या सभी पर शक

नई दिल्ली/कोलकाता, एजेंसी। चुनाव आयोग ने बुधवार को माना कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में तकनीकी गड़बड़ी हो गई थी। डिस्प्ले एरर की वजह से वोटर्स का नाम जांच के दायरे में दिखा रहा था। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी टीम ने करीब 2 घंटे में समस्या ठीक कर दी। आयोग इस गड़बड़ी की जांच कर रहा है।

दरअसल एक दिन पहले मंगलवार शाम को बंगाल में जब कई लोगों ने अपना वोटर स्टेटस (EPIC नंबर से) चेक किया, तो उनके नाम के आगे (जांच के दायरे में) दिख रहा था। यह उन लोगों के साथ भी हुआ जिनका नाम पहले से ही फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल था।

सत्ताधारी पार्टी TMC ने इस पर सवाल

उठाए और कहा कि इससे ऐसा लग रहा था जैसे सभी वोटरों पर शक किया जा रहा हो। हालांकि चुनाव आयोग ने सिर्फ इसे टेक्निकल एरर बताया।

कांग्रेस नेता बोले- बीजेपी केरल में खाता नहीं खोल पाएगी

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को दावा किया कि बीजेपी केरल में खाता नहीं खोल पाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला बोलीं- राष्ट्र निर्माण लगातार होने वाली प्रक्रिया: ये रातोंरात नहीं होता

विपक्ष बैकों को गंभीर हालत में छोड़कर गया था

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण लगातार होने वाली प्रक्रिया है, यह रातोंरात नहीं होता है।

उन्होंने विपक्ष पर टिप्पणी में कहा- कोविड संकट का भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीमित असर पड़ा था। विपक्ष आज बातें कर रहा है, लेकिन ये डबल बैलेंस शीट छोड़कर गए थे। बैंकों को गंभीर हालत में छोड़ा था। आज जब हमारे बैंकों के हालात ठीक हैं, तो ये आलोचना कर रहे

हैं। सीतारमण ने कहा कि इनके दौर में लगातार 22 महीने महंगाई डबल डिजिट में रही, जो कि एक रिकॉर्ड है। इनके लिए गए कर्ज का ब्याज आज हम चुका रहे हैं। सुधार किसी मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि स्पष्टता, प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास के साथ दृढ़ विश्वास से किए जा रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 'सुधार एक्सप्रेस' पर सवार है।

सीतारमण बोलीं- विपक्ष केवल सवाल करता है, जबाव सुनने मौजूद नहीं रहता : वित्त मंत्री ने विधेयक के पेश किए जाने के दौरान विपक्ष को सदन में नहीं मौजूद रहने पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष सवाल करता है तो उसे जबाव सुनने के लिए सदन में मौजूद रहना चाहिए।

दरअसल, सदन में इस विधेयक का उद्देश्य आने वाले वित्त वर्ष के लिए सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करना है। चर्चा के बाद इसे पारित करने के लिए पेश किए जाने की उम्मीद है। वित्त मंत्री के दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए जाने की उम्मीद है। इस विधेयक का उद्देश्य दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 में और संशोधन करना है।

सुप्रीम कोर्ट बोला: पब्लिक इवेंट्स में वंदेमातरम अनिवार्य नहीं

कहा- जब इसके लिए सजा होने लगेगी, तब विचार करेंगे; याचिका खारिज

नई दिल्ली ,एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' गाने को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका कर दी। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्लेस और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जारी यह निर्देश अनिवार्य नहीं है। सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका समय से पहले दायर की गई है।

मामला CJI जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच में था। बेंच ने कहा कि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में वंदेमातरम न गाने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है।

बेंच ने कहा- ये दिशानिर्देश केवल एक प्रोटोकॉल हैं और इनका पालन करना अनिवार्य नहीं है। जब याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, या फिर उसके लिए

गाना अनिवार्य किया जाएगा, तब हम इन सब बातों पर ध्यान देंगे।

याचिकाकर्ता का दावा- सलाह देने के बहाने साथ गाने मजबूर किया जाएगाअदालत मुहम्मद सईद नूरी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। CJI ने कहा- 'हमें वह नोटिस दिखाइए जिसमें आपको राष्ट्रगान बजाने के लिए मजबूर किया गया है। आप एक स्कूल चलाते हैं, हमें यह भी नहीं पता कि वह मान्यता प्राप्त है या नहीं।'

भाजपा बोली- ओवैसी बंगाल में घुसने की कोशिश कर रहे यहां लोग किसी को जल्दी नहीं अपनाते

तमिलनाडु- AIADMK की 23 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी

नई दिल्ली/ कोलकाता/ चेन्नई, एजेंसी। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के लिए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के कोलकाता पहुंचने पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, ओवैसी लंबे समय से बंगाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं।

कई पार्टियां दूसरी जगहों पर सफल हुई हैं, लेकिन बंगाल में लोग किसी को जल्दी स्वीकार नहीं करते। उन्हें काम करना होगा, लड़ना होगा, फिर बंगाल उन्हें स्वीकार करेगा।

दरअसल, ओवैसी की पार्टी ने बंगाल में पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी से गठबंधन किया है।

उधर तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के थिरुप्पराईथुराई में 50 से ज्यादा परिवारों ने इस बार विधानसभा चुनावों के बॉयकॉट का ऐलान किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 16 साल से वे बिना बिजली, पानी और टॉयलेट के रह रहे हैं।

असम चुनाव- 815 उम्मीदवारों का नामांकन, 776 कैंडीडेट का पर्चा सही : असम की 124 विधानसभा सीटों के लिए 776 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर वैलिड पाए गए। असम के जॉइंट चीफ इलेक्शन ऑफिसर के मुताबिक, बची हुई दो सीटों, बारपेटा (SC) और ढेकियाजुल के लिए पेपर्स की जांच बुधवार को पूरी हो जाएगी।

असम के जॉइंट चीफ इलेक्शन ऑफिसर के मुताबिक, असम विधानसभा के आम चुनाव, 2026 के लिए नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी की गई। हालांकि, 126 सीटों में से 124 सीटों पर स्क्रूटनी पूरी हो चुकी है। 24 बारपेटा SC और 65 ढेकियाजुली के लिए स्क्रूटनी 25 मार्च 2026 को सुबह 11 बजे तक टाल दी गई है। 124 सीटों के 776 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन वैलिड पाए गए हैं। असम विधानसभा 2026 के आम चुनाव के लिए कुल 815 उम्मीदवारों ने 1389 नॉमिनेशन फाइल किए थे।

कांग्रेस को नोटिस: अकबर रोड-रायसीना हिल्स का दफ्तर खाली करें

28 मार्च तक का वक्त; दावा- एस्टेट डिपार्टमेंट के खिलाफ कोर्ट जाएगी पार्टी

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस पार्टी को 24 अकबर रोड वाला दफ्तर 28 मार्च तक खाली करना होगा। एस्टेट डिपार्टमेंट ने पार्टी को नोटिस दिया है। न्यूज एजेंसी ANI ने कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कहा है कि दफ्तर खाली करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है।

हालांकि, कांग्रेस का हेडक्वॉर्टर पहले ही यहां से इंदिरा भवन शिफ्ट हो चुका है। पार्टी इस बंगले को खाली नहीं करना चाहती है।

उधर, एस्टेट डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के 5 रायसीना हिल्स रोड स्थित इंडियन यूथ कांग्रेस (आईवाईसी) के कार्यालय के लिए भी एक और नोटिस जारी किया है।

कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि कांग्रेस,

कांग्रेस का दफ्तर 2025 में 24 अकबर रोड से इंदिरा भवन में शिफ्ट

कांग्रेस ने 14 जनवरी 2025 को ही अकबर रोड वाले ऑफिस से अपना दफ्तर इंदिरा भवन में शिफ्ट किया है। 46 साल बाद पार्टी ने अपना पता बदला था। इंदिरा भवन की आधारशिला 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने रखी थी। इसे बनने में 252 करोड़ रुपए लगे।

सरकार के इस रवैए के खिलाफ कोर्ट में अपील करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि 1 अशोक रोड या पंत मार्ग वाले BJP के दफ्तर भी खाली नहीं करवाए गए हैं।

अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में बेंगलुरु में एफआईआर

- **भतीजे रोहित ने 5 आरोप लगाए, कहा- महाराष्ट्र में शिकायत दर्ज नहीं की गई**

बेंगलुरु, एजेंसी। महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के मामले में बेंगलुरु में जीरो FIR दर्ज की गई है। FIR उनके भतीजे और एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार की शिकायत पर दर्ज हुई है। उन्होंने हादसे को आपराधिक साजिश

बताया है। उन्होंने FIR में 5 मुख्य आरोप लगाए हैं।

रोहित ने कहा कि उन्होंने मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन, बारामती पुलिस और महाराष्ट्र CID से संपर्क किया, लेकिन कहीं भी FIR दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने 23 मार्च को बेंगलुरु में जीरो पर FIR दर्ज कराई। जहां अपराध हुआ है उसे छोड़कर देश के किसी भी थाने में उस अपराध की FIR दर्ज कराई जाती है तब उसे जीरो FIR कहते हैं। इसे फिर संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कर्नाटक पुलिस ने केस दर्ज कर इसे महाराष्ट्र पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। दरअसल, 28 जनवरी को बारामती एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश में अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई थी।

कर्नाटक में पॉलिसी- बच्चों का स्क्रीन टाइम 1 घंटा रहे: शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद

9-12वीं के छात्रों के लिए ड्राफ्ट जारी

बैंगलोर, एजेंसी। कर्नाटक सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के डिजिटल इस्तेमाल को लेकर मंगलवार को ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है। इसमें सिफारिश की गई है कि पढ़ाई के अलावा मनोरंजन के लिए स्क्रीन टाइम रोजाना 1 घंटे तय किया जाए। शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद करने की भी सिफारिश की गई है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि छात्रों को सोने से एक घंटे पहले स्क्रीन से दूर रखा जाए। मोबाइल के लिए 'चाइल्ड प्लान' का सुझाव दिया गया है, जिसमें ऑडियो-ओनली विकल्प और तय समय के बाद इंटरनेट बंद करने की व्यवस्था होगी। उम्र के हिसाब से डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने की भी बात कही गई है। सरकार के मुताबिक, करीब 25% किशोरों में इंटरनेट की लत है, जिससे नींद की कमी, चिंता और ध्यान भटकने जैसी समस्याएं हो रही हैं। इसी को देखते हुए यह पॉलिसी लाई गई है।

कई संस्थानों के साथ मिलकर तैयार ड्राफ्ट : यह पॉलिसी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कर्नाटक स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, निमहांस और शिक्षा विभाग ने मिलकर तैयार किया है। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के 6 मार्च को जारी बजट में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर सख्ती के ऐलान से अलग है। **6 मार्च को कर्नाटक सरकार ने बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर बैन लगाया था :** कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने का ऐलान किया था। कर्नाटक ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। सीएम सिद्धारमैया ने बजट भाषण के दौरान कहा कि बच्चों में मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे उन पर गलत असर पड़ रहा है।

कुवैत के एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक, फ्यूल टैंक में आग लगी

इराकी लड़ाकों का अमेरिका के 23 ठिकानों पर हमला

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 26वां दिन है। ईरान ने मंगलवार रात कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट ड्रोन अटैक किया, जिससे वहां मौजूद फ्यूल टैंक में आग लग गई।

कुवैत की सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं धमाके की आवाज सुनाई दे रही है, तो वह दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने की वजह से है।

सेना ने लोगों से अपील की है कि वे सरकार के सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। इससे पहले कुवैत के नेशनल गार्ड ने

बताया कि उसने अपने इलाके में 5 ड्रोन मार गिराए हैं। वहीं, इराक के एक उग्रवादी समूह इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने कहा है कि उसने पिछले 24 घंटे में अमेरिका से जुड़े 23 ठिकानों पर हमले किए हैं। ग्रुप के मुताबिक, इन हमलों में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि, इन हमलों से कितना नुकसान हुआ, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

दक्षिणी लेबनान में इजराइल की एयरस्ट्राइक, 9 लोगों की मौत

लेबनान के दक्षिणी हिस्से में इजराइल के हमलों में 9 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सिदोन इलाके के पास कई जगहों पर हमले हुए। अदलौन इलाके में एक हमले में 4 लोगों की जान चली गई।

वहीं, मियेह मियेह शरणार्थी कैंप में एक इमारत पर हमला हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई और 4 लोग घायल हो गए। इसके अलावा, हब्बूश इलाके में हुए एक और हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग हो गए।

दिल्ली वालों को जलभराव से मिलेगी मुक्ति, सरकार ने 610 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में जलभराव की समस्या दशकों पुरानी है। 50 वर्ष से अधिक पुराने ड्रेनेज सिस्टम और अपर्याप्त नालों के कारण हर बरसात में शहर की सड़कें तालाब बन जाती हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026-27 के बजट में इस समस्या को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेते हुए कहा कि अब दिल्ली डूबेगी नहीं, उबरेगी। इसी यरेजना के तहत पांच विधानसभा क्षेत्रों में जलभराव से राहत दिलाने के लिए एमबी रोड पर 387 करोड़ की लागत से ड्रेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई है। 2026-27 में इस कार्य के लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग विभाग द्वारा 200 करोड़ के अतिरिक्त राशि खर्च कर जलभराव समाप्त करने के लिए अन्य परियोजनाएं शुरू की जाएगी। पश्चिमी दिल्ली के किराड़ी, मुंडका, बवाना और नांगलोई विधानसभा क्षेत्रों की जल-निकासी समस्या के समाधान के लिए रेलवे लाइन के समानांतर 221 करोड़ की लागत से 4.50 किलोमीटर लंबे ट्रंक ड्रेन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना उन इलाकों के लिए राहत की सांस लेकर आएगी जो वर्षों से बरसात में परेशान होते आए हैं। इस वर्ष तैमूर नगर, कैलाश नगर, किराड़ी और बवाना जैसे क्षेत्रों में नालों का पुनर्विकास किया जाएगा।

बाढ़ रोकने के लिए दीवार का भी प्रस्ताव : सरकार ने इस साल 22 लाख मीट्रिक टन से अधिक गाद हटाकर यमुना के ऐतिहासिक जलस्तर पर भी सुरक्षित प्रवाह सुनिश्चित किया है। पुराने रेलवे पुल से मजनू का टीला तक यमुना किनारे बाढ़ रोकने के लिए दीवार का भी प्रस्ताव इस बजट में है, जो एक महत्वपूर्ण योजना साबित होगी। इसी तरह लोहे के पुल से सराय काले खां तक यमुना पुस्ता को मजबूत किया जाएगा। इस तरह के कार्यों के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के लिए 610 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।

दिल्ली में तार होंगे भूमिगत, घटेंगी दुर्घटनाएं, बढ़ेगी सुरक्षा; बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान

नई दिल्ली, एजेंसी। दशकों से अटके, लटके और शासन की नजरों का इंतजार करती तारों की जालें अब भूमिगत होगी। तारों से मुक्ति मिलते ही दिल्ली और सुंदर, हादसा मुक्त और बेहतर हो सकेगी। इसके लिए सरकार ने शालीमार बाग और चांदनी चौक में शुरू हुई तारों को भूमिगत करने की योजना को पूरी दिल्ली में ले जाने का निर्णय किया है। बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रविधान करते हुए जब मुख्यमंत्री ने ''दिल्ली कहां गई तिरे कूचों की रौनकें, गलियों से सर झुका कर गुजरने लगा है'', शेर पढ़ा तो सभी विधायक मेज थपथपाने लगे। क्योंकि, यह समस्या गंभीर है और हर दिल्ली वाला उससे परेशान और खौफ के साए में है। पुरानी दिल्ली की कई गलियों, कूचों में तो तारों के मकड़जाल से आसमान नहीं दिखता। गत दिनों पूर्व मुख्यमंत्री ने चांदनी चौक की ऐतिहासिक 28 सड़कों और गलियों में लटकते बिजली के तारों को टाने के लिए लगभग 160 करोड़ रुपये की लागत से 52.5 किमी लंबी ओवरहेड तारों को भूमिगत करने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। इस तरह की योजना शालीमार बाग में भी लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में हाई और लोवर टेंशन लाइन को भूमिगत किया जाएगा। यह दिल्ली की सुंदरता को भी बढ़ाएगा और दुर्घटनाओं से सुरक्षा भी देगा।

पंजाबी बाग में दिल्ली पुलिस के SI ने सड़क पर काम रही महिला को कार से मारी टक्कर

नई दिल्ली, एजेंसी। पंजाबी बाग थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें एक मारुति ब्रेज़ा कार ने सड़क पर सफाई कर रही एक महिला मजदूर को टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। आरोपित कार चालक दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसा सोमवार देर रात रात करीब 1:30 बजे वशिष्ठ कुमार गुल्ला मार्ग और नाथ एवेन्यू रोड के पास हुआ। यहां सड़क निर्माण और सफाई का कार्य चल रहा था। 45 वर्षीय महिला कामगार धर्मवती जब सेंट्रल वर्ज के पास सफाई कर रही थीं, तभी एक बेकाबू ब्रेज़ा कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि धर्मवती गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें तुरंत पास के आचार्य भिक्षु अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। आरोपित कार चालक का नाम लकी है, जो दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर है और रंजीत नगर थाने में तैनात है। हादसे के वक्त वह ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था। पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त डीएस भास्कर ने बताया कि घटना के तुरंत बाद आरोपित सब-इंस्पेक्टर खुद घायल महिला को अपनी कार में लेकर आचार्य भिक्षु अस्पताल पहुंचा, लेकिन इलाज के दौरान धर्मवती ने दम तोड़ दिया। पूछताछ में आरोपित एसआई ने पुलिस को बताया कि घटनास्थल पर मशीन से सड़क की खोदाई की गई थी, जिसके कारण वहां काफी धूल उड़ रही थी। उसने खड़े होकर झाड़ू लगाने वाले कामगारों को देखने के बाद कार को किनारे से निकालने की कोशिश की, लेकिन धूल की वजह से वह नीचे बैठकर झाड़ू लगा रही धर्मवती को नहीं देख पाया।

सोनिया गांधी सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, एक्सपर्ट डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा इलाज

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को सीने में इंफेक्शन की शिकायत के बाद मंगलवार देर रात करीब 11:15 बजे सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल पहुंचने पर शुरुआती जांच के बाद उन्हें तुरंत इंटेंसिव केयर पर भर्ती कर विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक सोनिया गांधी अस्पताल के स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की टीम की निगरानी में हैं और उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। उन्हें आब्जरवेशन में रखा गया है। अस्पताल प्रशासन ने संकेत दिया है कि उनकी स्थिति को लेकर बुधवार सुबह विस्तृत मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा सकता है।

बजट में हरित दिल्ली पर जोर, पर्यावरण पर 21% होगा खर्च

सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी घोषणाएं

नई दिल्ली, एजेंसी। ट्रिपल इंजन सरकार के रथ पर सवार रेखा गुप्ता सरकार ने अपने कार्यकाल के दूसरे बजट में एक लाख करोड़ से अधिक के बजटीय प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए दिल्ली के विकास की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की है। साथ ही इसे ग्रीन बजट बताते हुए इसका 21 प्रतिशत से अधिक पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं के लिए आवंटित किया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत एक लाख, तीन हजार 700 करोड़ के ग्रीन बजट में से 22,236 करोड़ रुपये राजधानी को हरित दिल्ली के रूप में विकसित करने पर खर्च किए जाएंगे। हरित विकास के साथ ही बजट में आधारभूत ढांचा मजबूत करने पर जोर देते हुए तेज विकास करने को प्रमुखता दी गई है। वहीं, सभी को स्वच्छ पेयजल, लोगों को आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास से भविष्य निर्माण, महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग का सशक्तीकरण, जाममुक्त दिल्ली, बेहतर परिवहन सेवा, भ्रष्टाचार रहित जवाबदेह प्रशासन, नवाचार से रोजगार सृजन व आधुनिकता के साथ विरासत को संजोने के प्रयासों पर भी जोर दिया गया है। आप के चार विधायकों का निलंबन वापस न लेने के विरोध में विपक्ष के बहिष्कार के बीच मंगलवार को विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का बजट प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ, हरित व सशक्त दिल्ली सिर्फ वादा नहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी है। जहां हर नागरिक का सम्मान और हर सपने का उत्थान होगा। दिल्ली को सिर्फ ईंट-पत्थरों का नगर नहीं, हरियाली व अवसरों का शहर बनाने पर काम हो रहा है।

बीते समय में भ्रष्टाचार, अदूरदर्शिता और मुफ्त सुविधाओं की संस्कृति से वृद्धि दर प्रभावित हुई है। यही कारण है कि वर्ष 2018 से 2020 के बीच विकास की गति रुकी हुई थी, लेकिन आज दिल्ली एक निर्णायक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। अब नीतियां केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि धरातल पर परिणाम देती हैं। आज दिल्ली ट्रिपल इंजन की शक्ति से तेज गति से दौड़ रही है। प्रकृति के साथ ही प्रगति है, इसे सरकार भलीभांति समझती है और बजट में भी इसका ध्यान रखा गया है। विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली की गिनती होती है। इस कलंक को दूर करने के लिए बजट में कदम उठाए गए हैं।

ड्रोन नीति बनाकर ग्रीन रोजगार को बढ़ावा देने की घोषणा : बजट प्रस्तावों में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के उद्देश्य से नई सड़कें और फ्लाईओवर के निर्माण से लेकर, पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था, स्वच्छता, धूल नियंत्रण, ठोस व ई कचरा निस्तारण और स्वच्छ ऊर्जा के लिए बजट में धनराशि आवंटित की गई है। साथ ही सेमी कंडक्टर और ड्रोन नीति बनाकर ग्रीन रोजगार को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। बजट में सरकार ने सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है। साथ ही राजधानी की महिलाओं को भी यह दिखाने का प्रयास किया है कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रयासरत हैं और उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। चुनावी घोषणा महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ का आवंटन करते हुए रेखा ने कहा कि पात्र महिलाओं को 2500 रुपये मिलने लगेंगे, इस योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल जल्द खोला जाएगा।

लखपति बिटिया योजना के लिए 128 करोड़ का प्रावधान : खपति बिटिया योजना के लिए 128 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हुनरमंद महिलाओं के लिए रानी हाट बनाने के साथ ही एक हजार महिलाओं को ई-ऑटो के परमिट दिए जाएंगे। महिला सुरक्षा के लिए 50 हजार नए सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही पुराने सीसीटीवी कैमरों की एएमसी दी जाएगी और एलईडी लाइटें लगाकर सड़कों पर डार्क स्पाट खत्म किए जाएंगे। नौवीं कक्षा में आने वाली एक लाख 30 हजार छात्राओं को साइकिल व दसवीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटाप देने की भी घोषणा की गई है।

130 करोड़ रुपये खर्च कर वन क्षेत्र का विकास: केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली में विकास की गति को तेज करने के लिए इस बजट में आधारभूत ढांचे के विकास, महिला सशक्तीकरण, पेयजल आपूर्ति, यमुना की सफाई, समावेशी विकास सहित 10 क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण और आपातकालीन उपाय योजना की घोषणा की गई है। पर्यावरण और वन क्षेत्रों के लिए पिछले वर्ष के 505 करोड़ की तुलना में इस बार 822 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 130 करोड़ रुपये खर्च कर वन क्षेत्र का विकास होगा ।

मेट्रो के लिए बजट में 2885 करोड़ रुपये का प्रावधान: मेट्रो के चरण चार व पांच के लिए बजट में 2885 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली-एसएनबी शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड़ और दिल्ली-सोनीपत-पानीपत नमो ट्रेन को मंजूरी दे दी है। बजट में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के लिए 568 करोड़ का प्रविधान किया गया है। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली के बड़े नालों सोलर पैनल लगाने की भी घोषणा की गई है।

दिल्ली को मिलेगा अपना सदन, 'ट्वीन टावर' नाम से बनेगा नया सचिवालय'

बजट में सरकार का एलान

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय राजधानी में जहां देश के विभिन्न राज्यों के सदन हैं पर अपना कोई नहीं है। लेकिन अब दिल्ली को भी अपना सदन मिलेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के बजट में इसकी घोषणा की है। दिल्ली सदन के लिए 10 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। इससे दिल्ली आने वाले पर्यटकों और आगंतुकों के रहने की व्यवस्था होगी। साथ ही यहां पर कैंटीन भी होगी। सरकार दिल्ली सदन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बने आवास को भी दिल्ली सदन के तौर पर विकसित कर सकती है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार का आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नया सचिवालय भी बनेगा। जिलों की संख्या बढ़ने और जिलों में नागरिकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए मिनी सचिवालय तैयार किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने दक्षिण-पश्चिम जिले के लिए द्वारका में पहले मिनी सचिवालय की 213 करोड़ की परियोजना पूर्व में मंजूर कर दी थी। जबकि शेष सचिवालयों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रविधान किया गया है। मिनी सचिवालयों में जिला प्रशासन का आधुनिक दफ्तर होगा। वहीं, यहां पर संपत्ति पंजीकरण, जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य कार्यों के लिए आने वाले लोगों को एक ही छत के नीचे सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालय होने से होने वाली परेशानी को देखते हुए सचिवालय बनाया जाएगा। फिलहाल इसके लिए दिल्ली सरकार जगह की तलाश कर रही है और केंद्र सरकार से भी जमीन मांग रही है। वहीं, इसके समांतर आइटीओ स्थित लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मुख्यालय को तोड़कर ट्वीन टावर के तौर पर सचिवालय विकसित करने पर काम कर रही है। यह बहुमंजिला होगा। जहां पर दिल्ली सरकार के सभी विभाग होंगे। फिलहाल दिल्ली सचिवालय आइटीओ के पास ही आईजीआई स्टेडियम के पास प्लेयर्स बिल्डिंग में संचालित होता है। लेकिन इसमें सभी विभागों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। इसकी वजह से सिविल लाइंस और आइटीओ पर कई विभागों के दफ्तर संचालित होते हैं। दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण के लिए लोगों को दलालों के चक्कर नहीं काटने होंगे। बल्कि इसकी व्यवस्था पारदर्शी होगी। इसके लिए दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण के लिए सब रजिस्ट्रार आफिस को पासपोर्ट आफिस की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।

दिल्ली में अवैध रूप से रह रही थी बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार

बाहरी दिल्ली, एजेंसी। उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस की विदेशी सेल ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शालीमार बाग क्षेत्र से एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए देश से निष्कासन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने महिला के कब्जे से एक स्मार्ट फोन बरामद किया है, जिसमें प्रतिबंधित आईएमओ ऐप इंस्टॉल मिला। इसके अलावा मोबाइल गैलरी में बांग्लादेशी पहचान से जुड़े दस्तावेज भी पाए गए, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। पकड़ी गई महिला की पहचान मीतू अख्तर (28) के रूप में हुई है, जो ढाका (बांग्लादेश) की रहने वाली है। उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि विदेशी सेल की टीम ने इंस्पेक्टर विपिन कुमार और एसीपी राजीव कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 23 मार्च की सुबह विशेष अभियान के तहत गठित टीम ने जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन और आजादपुर मंडी क्षेत्र में छापेमारी की। लंबे समय तक तलाश के बाद मैक्स अस्पताल के पास एक संदिग्ध महिला को पकड़ा गया।

अमेरिका को होर्मुज की नाकाबंदी करनी चाहिए', पूर्व एनएसए बोल्टन का बड़ा बयानढ भारत का भी किया जिक्र

वॉशिंगटन, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। इस बातचीत के बाद अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान के तेल राजस्व को खत्म करने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी करनी चाहिए। जॉन बोल्टन ने आकलन किया कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत में क्षेत्रीय संघर्ष और ईरानी ऊर्जा पर भारत की निर्भरता पर बात हुई होगी। जॉन बोल्टन ने कहा, 'मुझे लगता है कि पीएम मोदी की सोच साफ है कि वे ईरान से तेल खरीदने के इच्छुक हैं। आज सुबह दो भारतीय जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से निकले भी हैं। हालांकि इस लेन-देन का असर भू-राजनीति पर पड़ता है।' बोल्टन ने कहा कि 'इस तरह राजस्व का प्रवाह क्षेत्रीय सैन्य संतुलन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है और इससे ईरान को राजस्व मिलता है और उसकी युद्ध मशीन चलती रहती है।'

'अमेरिका को होर्मुज की नाकाबंदी करनी चाहिए': जॉन बोल्टन ने कहा, 'पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत में भारत की ऊर्जा जरूरतों को ईरान की बजाय एक स्थायी स्त्रोत पर स्थानांतरित करने पर भी बात हुई होगी।' बोल्टन ने कहा कि 'अमेरिका को ईरान के राजस्व स्त्रोतों को बाधित करने की जरूरत है और इसके लिए मुझे लगता है कि अमेरिका को होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी करनी चाहिए। ताकि ईरान का निर्यात बाधित हो।'

टोक्यो में चीनी दूतावास में घुसने के आरोप में जापानी सैनिक गिरफ्तार

टोक्यो, एजेंसी। जापान के अधिकारियों ने बुधवार को एक जापानी सैनिक को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। इस सैनिक पर कथित रूप से टोक्यो में चीनी दूतावास में बिना इजाजत (अवैध रूप) से घुसने का आरोप है। चीन ने इस घटना पर विरोध जताया था, जिसके एक दिन बाद यह गिरफ्तारी हुई है। अब यह मामला जापान और चीन के बीच बढ़ते तनाव का नया केंद्र बन गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बीजिंग में एक मीडिया वार्ता के दौरान बताया कि मंगलवार सुबह एक व्यक्ति दीवार फांदकर दूतावास परिसर में जबरन घुस आया। उस व्यक्ति ने खुद को जापानी आत्म-रक्षा बल का अधिकारी बताया था। टोक्यो पुलिस ने बुधवार को जानकारी दी कि गिरफ्तार व्यक्ति की उम्र 23 साल है और वह जापान की थल सेना (जीएसडीएफ) का सदस्य है। जापानी सेना ने पुष्टि की है कि संदिग्ध सैनिक मियाजाकी प्रांत के कैंप एबिनो में तैनात है। सेना के अधिकारी इस मामले में पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं। जापानी मीडिया ने पुलिस के हवाले से बताया कि यह सैनिक चीनी राजदूत को यह कहने के लिए दूतावास में घुसा था कि चीन जापान के प्रति अपना कड़ा रुख बंद करे। सैनिक के पास एक चाकू भी था। उसने धमकी दी थी कि अगर उसकी मांग नहीं मानी गई, तो वह खुद को मार लेगा। जापान के सरकारी चैनल एनएचके के अनुसार, उस व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया गया और आगे की जांच के लिए टोक्यो पुलिस को सौंप दिया गया। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, उस व्यक्ति ने कथित तौर पर दूतावास की दीवार फांदी थी और वहां एक चाकू भी मिला है।

ट्रंप की लोकप्रियता घटी: ईरान जंग और महंगाई के बीच गिरकर 36 प्रतिशत पहुंची

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटकर 36 प्रतिशत रह गई है। यह उनके दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद का सबसे कम स्तर है। यह जानकारी रॉयटर्स/इप्सोस के एक सर्वे में सामने आई है। चार दिन तक चले इस सर्वे में पाया गया कि ट्रंप के कामकाज से संतुष्ट लोगों की संख्या 40 प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत रह गई है। ईंधन की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी और ईरान के साथ युद्ध को लेकर लोगों की नाराजगी का असर ट्रंप की लोकप्रियता पर पड़ा है। अमेरिका और इस्राइल के 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे लोगों का खर्च बढ़ा है। महंगाई और रोजमर्रा के खर्च को लेकर भी लोगों की नाराजगी सामने आई है। केवल 25 प्रतिशत लोगों ने माना कि ट्रंप महंगाई को संभालने में ठीक काम कर रहे हैं। ईरान पर हमलों को लेकर भी लोगों की राय बंटी हुई है। 35 प्रतिशत लोगों ने इन हमलों का समर्थन किया, जो पिछले सर्वे के 37 प्रतिशत से कम है। वहीं 61

ईरान युद्ध का झटका: नए घरों में सोलर पैनल और हीट पंप अनिवार्य, ब्रिटेन का फैसला

लंदन, एजेंसी। ईरान युद्ध से पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच ब्रिटेन ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इंग्लैंड में बनने वाले सभी नए घरों में सोलर पैनल और हीट पंप अनिवार्य करने का एलान किया है, ताकि जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाई जा सके। ब्रिटेन सरकार ने मंगलवार को नए नियम पेश करते हुए स्पष्ट किया कि यह कदम नीति-निर्माताओं की ओर से ईरान युद्ध के आर्थिक और ऊर्जा प्रभावों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। सरकार के अनुसार, यह पहल फ्यूचर होम्स स्टैंडर्ड का हिस्सा है, जो 2028 से लागू होगा। इस मानक के तहत सभी नए घरों में ऑन-साइट रिन्यूएबल बिजली उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख भूमिका सौर ऊर्जा की होगी। साथ ही, घरों में लो-कार्बन हीटिंग सिस्टम जैसे हीट पंप और हीट नेटवर्क को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। ब्रिटेन के ऊर्जा मंत्री एड मिलिबैंड ने कहा, ईरान युद्ध ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा सरकार का लक्ष्य जीवाश्म ईंधन बाजारों की पकड़ से बाहर निकलना है, जिन पर देश का नियंत्रण नहीं है। मिलिबैंड ने यह भी बताया कि सरकार न केवल नए घरों में सोलर पैनल को मानक बना रही है, बल्कि आने वाले महीनों में दुकानों पर प्लग-इन सोलर पैनल भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें लोग अपने घरों की बालकनी में आसानी से स्थापित कर सकेंगे।

ऊर्जा सुरक्षा बनाम घरेलू उत्पादन इस फैसले को लेकर ब्रिटेन की घरेलू राजनीति में भी बहस तेज हो गई है। विपक्षी कंजरवेटिव पार्टी की शैडो एनर्जी सेक्रेटरी क्लेयर कुटिन्हो ने सरकार से नॉर्थ सी में नए तेल और गैस क्षेत्रों के लाइसेंस जारी करने की मांग की है, ताकि घरेलू ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाकर उपभोक्ताओं के बिल कम किए जा सकें। यह बहस इस बात को रेखांकित करती है कि ऊर्जा संकट से निपटने के लिए देशों के सामने दो विकल्प हैं, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेज बदलाव या पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना।

कभी मेल बैलेट के विरोधी रहे ट्रंप ने खुद इसी से किया मतदान

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फ्लोरिडा में मेल बैलेट के जरिए अपना वोट डाला है। जबकि वे सार्वजनिक रूप से इस मतदान तरीके को धोखाधड़ी का जरिया बताते हैं और कांग्रेस से इसे सीमित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने खुद इसी तरीके का इस्तेमाल किया। पाम बीच काउंटी के रिकॉर्ड से पता चला है कि राष्ट्रपति ने मंगलवार को राज्य विधानसभा सीटों के लिए हुए विशेष चुनाव में मेल से वोट दिया और उनके वोट की गिनती भी हो गई है। ट्रंप के समर्थन के बावजूद उनके रिपब्लिकन उम्मीदवार यहां से चुनाव हार गए है। यहां डेमोक्रेट की एमिली ग्रेगरी ने जीत हासिल की है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप 'यूनिवर्सल मेल-इन वोटिंग' के खिलाफ हैं, न कि उन व्यक्तिगत मामलों के जहां मतदाता को इसकी जरूरत होती है। वेल्स के अनुसार, ट्रंप जिस 'सेव अमेरिका एक्ट' का समर्थन करते हैं, उसमें बीमारी, विकलांगता, सेना या यात्रा जैसी स्थितियों में मेल से वोट देने की छूट दी गई है। उन्होंने कहा यूनिवर्सल मेल-इन वोटिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है। उन्होंने कहा कि ट्रंप फ्लोरिडा के निवासी हैं लेकिन वे वाशिंगटन में रहते हैं, इसलिए उनका मेल से वोट देना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बावजूद, ट्रंप ने पिछले हफ्त मेल-इन वोटिंग को धोखाधड़ी और बेहद भ्रष्ट बताया था। वे कांग्रेस से 'सेव एक्ट' पास करने का आग्रह कर रहे हैं ताकि मेल मतदान के विकल्पों को बहुत सीमित किया जा सके। हालांकि, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार, मेल मतदान में धोखाधड़ी के मामले न के बराबर हैं। रिपोर्ट बताती है कि हर एक करोड़ वोटों में से सिर्फ चार मामलों में ही गड़बड़ी पाई गई है। सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने ट्रंप के इस कदम की आलोचना की है। शूमर ने कहा कि ट्रंप के अनुसार जब दूसरे लोग मेल से वोट दें तो वह 'धोखाधड़ी' है, लेकिन जब वे खुद ऐसा करें तो वह सही है। ट्रंप 2020 के चुनाव में अपनी हार के बाद से ही मेल मतपत्रों पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि, अमेरिकी अदालतों और उनके खुद के अटॉर्नी जनरल को चुनाव नतीजों को प्रभावित करने वाली किसी धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं मिला।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में 'मार्केट रिसर्च टूल्स एंड मार्केट प्रोडक्ट फिट' पर प्रशिक्षण संपन्न

छात्रों और युवा उद्यमियों को बाजार की समझ व स्टार्टअप विकास के गुर सिखाए गए

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, संजय गांधी स्मृति शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इन्क्यूबेशन सेंटर में 'ट्रेनिंग ऑन मार्केट रिसर्च टूल्स एंड मार्केट प्रोडक्ट फिट विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रभाकर सिंह ने की कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों युवा उद्यमियों और स्टार्टअप की दिशा में कार्य करने के इच्छुक युवाओं को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना था ताकि वे अपने नवाचारों को बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित कर सकें और उन्हें

सफल उद्यम में परिवर्तित कर सकें। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्य डॉ. प्रभाकर सिंह ने कहा कि इन्क्यूबेशन सेंटर छात्रों में उद्यमिता की भावना विकसित करने का एक सशक्त मंच है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धी युग में सफल उद्यमिता के लिए बाजार अनुसंधान और उत्पाद-बाजार अनुकूलता (मार्केट प्रोडक्ट फिट) की गहरी समझ अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने मुख्य वक्ता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए छात्रों से अपील की कि वे प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने भविष्य के स्टार्टअप में करें कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अभिलाष मेराबी, महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र ने अपने उद्बोधन में बाजार अनुसंधान के आधुनिक टूल्स, डेटा संग्रहण एवं विश्लेषण की तकनीकों, उपभोक्ता व्यवहार की समझ तथा उत्पाद को बाजार की मांग के अनुरूप विकसित करने की रणनीतियों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने साथ ही जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, सरकारी सहायता और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के बारे में भी प्रतिभागियों को अवगत कराया इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापकगण डॉ. के. एस. नेताम (विभागाध्यक्ष, भूगोल), डॉ. राकेश कुमार प्रजापति (नोडल अधिकारी, इन्क्यूबेशन सेंटर), और अरविंद सोनी सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

अफवाहों से रहें सतर्क पेट्रोल-डीजल की पर्याप्त उपलब्धता प्रशासन ने किया आश्वस्त

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए आमजन को आश्वस्त किया है कि जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है मध्यप्रदेश शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट सभागार सीधी में अपर कलेक्टर बी.पी. पाण्डेय की अध्यक्षता में जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई बैठक में वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति, उपलब्धता और खपत की विस्तृत समीक्षा की गई बैठक में प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी प्रियल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारु रूप से संचालित हो रही है उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है और सभी पेट्रोल पंपों पर नियमित रूप से ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है अपर कलेक्टर पाण्डेय ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए कि वे ईंधन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखें और आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने दें उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि अनावश्यक भंडारण या कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए।

तीन जंगली हाथी घुसे,10 किमी चलकर पश्चिमी कटौतिया पहुंचे, फसल-मकान को नुकसान

मीडिया ऑडीटर, शहडोल (निप्र)। अनूपपुर जिले से भटककर आए तीन जंगली हाथी अब जिले के बुढार वन परिक्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं हाथियों की मौजूदगी के कारण वन विभाग अलर्ट पर है और उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है वन विभाग ने हाथियों की निगरानी के लिए दो विशेष टीमें गठित की हैं जिनमें कुल 15 कर्मचारी तैनात हैं इन टीमों की जिम्मेदारी बुढार रेंजर सलीम खान और केशवाही रेंजर अंकुर तिवारी को सौंपी गई है जानकारी के अनुसार ये तीनों हाथी पिछले कुछ महीनों से अनूपपुर के जंगलों में विचरण कर रहे थे शहडोल की सीमा में प्रवेश करने के बाद इन्हें सबसे पहले बुढार वन परिक्षेत्र के अरझुली इलाके में देखा गया था बीती रात हाथियों ने लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय कर पश्चिमी कटौतिया के आरएफ 87 और 88 के जंगल क्षेत्र में डेरा डाल लिया रात के दौरान हाथियों ने खेतों में घुसकर करीब एक एकड़ फसल को नुकसान पहुंचाया इसके अतिरिक्त बुढार क्षेत्र के कठई गांव के जमुनिया टोला में पंकू सिंह के घर में भी तोड़फोड़ की गई हाथियों ने घर में रखा महुआ और धान खा लिया जिससे ग्रामीण को आर्थिक क्षति हुई है हाथियों की गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग आसपास के गांवों में मुनादी करवा रहा है ग्रामीणों को सतर्क रहने रात में खेत या जंगल की ओर न जाने और हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाथी अपने पुराने कॉरिडोर के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं और संभावना है कि वे छत्तीसगढ़ की ओर लौट सकते हैं वन अमला उनकी निरंतर निगरानी में जुटा हुआ है।

400 ग्राम पंचायतों में गूंजा नशा मुक्ति का संकल्प, 50 हजार से अधिक लोगों ने ली शपथ

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार कलेक्टर के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ के मार्गदर्शन में जिले में व्यापक स्तर पर नशा मुक्ति जन-जागरूकता अभियान का सफल आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत जिले की 400 ग्राम पंचायतों, 5 नगरीय निकायों, विभिन्न जनपद पंचायतों, शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों और विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली अभियान के दौरान लगभग 50,000 से अधिक नागरिकों ने ऑफलाइन नशा मुक्ति की शपथ लेकर समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया

कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया और स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया इस क्रम में पीएम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पनवार में भी नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धनंजय मिश्रा, संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. दिलीप सोनी और बीआरसी राजेश पांडे की गरिमामयी उपस्थिति रही कार्यक्रम में विद्यालय की प्राचार्य, शिक्षकगण एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी-कर्मचारी जैसे चंद्र प्रताप तिवारी, दीपक कोल, रामनिहोर केवट, बाल सुधा मिश्रा तथा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के शिवांशु शुक्ला ने सक्रिय सहभागिता दिखाई बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एवं ग्रामीणजन भी उपस्थित रहे कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं रजनीश कुशवाहा, श्रुति गुप्ता और कंचन जायसवाल ने नशा मुक्ति पर प्रभावशाली भाषण प्रस्तुत किए। वहीं, बाल सुधा मिश्रा द्वारा प्रस्तुत प्रेरणादायक गीत ने कार्यक्रम को भावनात्मक एवं प्रेरक बना दिया अंत में सभी उपस्थित नागरिकों ने सामूहिक रूप से नशा मुक्ति की शपथ ली अभियान ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के साथ-साथ विशेष रूप से युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता साबित की है।

4309 बिजली कनेक्शनों का भुगतान वर्षों से लंबित , 19.77 करोड़ बकाया

मीडिया ऑडीटर, शहडोल (निप्र)। विभिन्न सरकारी विभागों पर बिजली कंपनी का कुल 19.77 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 4309 सरकारी कनेक्शनों पर यह भुगतान लंबे समय से लंबित बना हुआ है कुल बकाया राशि में से 16.34 करोड़ रुपए पुराना बकाया (एरियर) है जबकि वर्तमान बिल की राशि 2.94 करोड़ रुपए दर्ज की गई है बकायेदारों की सूची में ग्राम पंचायत विभाग शीर्ष पर है जिसकी 1204 पंचायतों पर 7.80 करोड़ रुपए बकाया हैं इसमें 6.55 करोड़ रुपए का एरियर शामिल है दूसरे स्थान पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है जिस पर 5.66 करोड़ रुपए की देनदारी है विभाग का पुराना बकाया 5.03 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है कल्याणकारी और शिक्षा विभागों पर भी लाखों की देनदारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के 971 कनेक्शनों पर 2.06 करोड़ रुपए लंबित हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के 695 कनेक्शनों पर 1.04 करोड़ रुपए का बकाया है इसके अतिरिक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पर 72.27 लाख नगर परिषद पर 63.16 लाख और स्कूल शिक्षा विभाग पर 26.20 लाख रुपए का बिल शेष है वित्तीय आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल बकाया का लगभग 82 प्रतिशत हिस्सा केवल पुराना एरियर है राजस्व, गृह, वन, बीएसएनएल और उच्च शिक्षा जैसे विभागों पर भी 13 से 17 लाख रुपए के बीच बकाया है कृषि, वित्त, सहकारिता और लोक निर्माण विभाग सहित कई अन्य कार्यालयों ने भी वर्षों से बिलों का भुगतान नहीं किया है।

10 गायों की भूख-प्यास से मौत 40 गौवंश बचाए गए; हंगामे के बाद जांच के आदेश

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। पनवार सेंगरान ग्राम पंचायत में बड़ी लापरवाही सामने आई है यहां एक अस्थायी बाड़े में बंद 10 गायों की भूख और प्यास से मौत हो गई घटना के बाद गांव में नाराजगी का माहौल है और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं सूचना मिलने पर शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे और गौरक्षा दल के केशव मिश्रा अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे उन्होंने बाड़े में बंद करीब 40 अन्य गायों को बाहर निकाला मृत गायों को बाद में दफनाया गया।

खाने-पीने की नहीं थी कोई व्यवस्था: विवेक पांडे ने आरोप लगाया कि पंचायत ने आवारा मवेशियों को बाड़े में तो बंद कर दिया लेकिन उनके लिए खाने और पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई ग्रामीण राधेश्याम कोल ने बताया कि मवेशी करीब 15 दिनों से बाड़े में बंद थे और तेज धूप में परेशान हो रहे थे

शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई: ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सचिव और जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार सूचना दी गई लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया इसी वजह से यह स्थिति बनी और 10 गायों की जान चली गई। वहीं ग्राम पंचायत सचिव इंदु सिंह ने इस मामले से अनजान होने की बात कही है उन्होंने आरोपों को गलत बताया और कहा कि उन्हें ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि उन्हें पहले इस घटना की जानकारी नहीं थी अब मामले में सचिव को नोटिस जारी किया जाएगा और अधिकारियों को मौके पर भेजकर जांच कराई जाएगी।

एलपीजी के लिए लाइन में लगे लोग; बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रहे घरेलू सिलेंडर

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए गैस रिफिल सेंटर पर लोगों की लंबी कतार लग रही है लोगों का कहना है कि इसके बावजूद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं जबकि एजेंसी संचालकों ने बताया कि जिले में घरेलू एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है लोग घबराहट में एक साथ एजेंसी पहुंच रहे हैं जिससे कतारें लंबी हो रही हैं गैस एजेंसियों की डिलीवरी व्यवस्था चरमराने से उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश है कई उपभोक्ताओं ने बताया कि समय पर बुकिंग कराने और मोबाइल पर 'सफलतापूर्वक डिलीवरी' का मैसेज आने के बाद भी सिलेंडर घर तक नहीं पहुंचा है स्थानीय निवासी राजेंद्र कुमार ने बताया कि मैसेज मिलने के हफ्तों बाद भी उन्हें गैस नहीं मिली है। बैढ़न स्थित गैस एजेंसियों और गोदामों पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की भीड़ जमा हो रही है उपभोक्ता सचिन दुबे ने बताया कि वह करीब चार घंटे से कतार में खड़े हैं लेकिन अब तक उन्हें सिलेंडर नहीं मिल सका है गैस न मिलने के कारण आम जनता को दैनिक कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है भारत गैस एजेंसी के संचालक एन.एम. शुक्ला ने स्पष्ट किया कि घरेलू एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है उन्होंने कहा कि लोग घबराहट में एक साथ एजेंसी पहुंच रहे हैं जिससे कतारें लंबी हो रही हैं हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई फिलहाल बंद है जिससे उसकी डिलीवरी प्रभावित हो रही है कमर्शियल गैस की सप्लाई रुकने से बढ़ी मुश्किल पिछले कुछ समय से बाधित है। इसके चलते होटल और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सामने संकट खड़ा हो गया है।

प्रशासनिक कार्यों में संवेदनशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश- विकास मिश्रा

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले में नवागत कलेक्टर विकास मिश्रा ने बुधवार को विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। मिश्रा वर्ष 2013 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं उनके पदभार ग्रहण करते ही जिला प्रशासन में नई कार्यशैली और प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्ट संदेश दिया गया पदभार संभालने के बाद कलेक्टर मिश्रा ने जिले के अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रारंभिक समीक्षा की उन्होंने जिले की प्रशासनिक स्थिति संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली तथा अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का

प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन की समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता, त्वरित कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रशासन का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना होना चाहिए कलेक्टर मिश्रा ने यह भी कहा कि जिले में विकास कार्यों को और गति दी जाएगी तथा सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा उन्होंने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी, अपर कलेक्टर बी.पी. पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर राजेश शुक्ला, उपखंड अधिकारी गोपद बनास राकेश शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

नवागत विकास मिश्रा का कलेक्ट्रेट निरीक्षण

व्यवस्थाओं में सुधार, स्वच्छता, पारदर्शिता और जनोन्मुखी कार्यप्रणाली पर दिया जोर

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। नवागत कलेक्टर विकास मिश्रा ने पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय के विभिन्न विभागों और शाखाओं का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने कार्यालयीन कार्यप्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने परिसर की साफ-सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुव्यवस्थित कार्यस्थल न केवल कार्यक्षमता को बढ़ाता है बल्कि आमजन के बीच प्रशासन की सकारात्मक छवि भी स्थापित करता है कलेक्टर मिश्रा ने कार्यालयों में फैले बिजली के तारों को व्यवस्थित करने और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण और रख-रखाव पर जोर देते हुए कहा कि सभी रिकॉर्ड अद्यतन और आसानी से उपलब्ध होने चाहिए ताकि कार्यों के निष्पादन में तेजी लाई जा सके उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने कक्षों में नेम प्लेट और पहचान पत्र (आईडी) अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें जिससे आम नागरिकों को संबंधित अधिकारी की पहचान करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि आमजन की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी निराकरण प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सभी अधिकारी समन्वय और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विभिन्न शाखाओं में जाकर कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कार्यालयीन व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार लाना समय की मांग है और इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।

खेत में मिली महिला की लाश, पति ने शक में पीट-पीटकर की हत्या

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सेमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बढ़ौरा में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है महिला का शव खलिहान में आपत्तिजनक अवस्था में मिला जिसके हाथ-पैर बंधे हुए थे पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया है जिसने चरित्र संदेह में हत्या करना स्वीकार किया है मृतका की मां मुन्नी ने बताया कि उसकी बेटी उमा रावत अपने पति मिथिला उर्फ ललवा रावत के साथ खलिहान में गेहूं की कटाई कर रही थी और रात में वहीं रुकती थी रात जब मां खलिहान पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गई उमा के हाथ-पैर बंधे हुए थे और शरीर पर चोटों के गंभीर निशान थे आरोपी ने वारदात के बाद शव को रजाई से ढंक दिया था वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार

हो गया जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था जिसके चलते उसने लाठी से पीट-पीटकर उसकी जान ले ली एसडीओपी चुरहट रवि प्रकाश कौल ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

पीएम संबोधन, 'ट्रंपी युद्धविराम'

संपादकीय

प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वक्तव्य देकर पश्चिम एशिया के संकट और संघर्ष को कोरोना महामारी जैसी गंभीर और अभूतपूर्व चुनौती माना है। उन्होंने देश की एकजुटता का आह्वान किया और इस आर्थिक, सुरक्षा संबंधी, मानवीय चुनौती को 'चुनौती' देने का हौसला दिया। प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त भी किया और जानकारी भी साझा की कि पहले हम 27 देशों से आयात करते थे, लेकिन अब 41 देशों से विविध सामान ले रहे हैं। देश में 53 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का 'रणनीतिक भंडार' है। उसे बढ़ा कर 65 लाख मीट्रिक टन करने पर काम किया जा रहा है। अब हम पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल का मिश्रण करते हैं, लिहाजा 4.5 करोड़ बैरल कम तेल आयात करना पड़ रहा है। यह प्रयोग सफल रहा है। रेलवे का लगभग 100 फीसदी बिजलीकरण किया जा चुका है, लिहाजा डीजल और कोयले की खपत नगण्य हो गई है। देश में खाद्यान्न के पर्याप्त भंडार हैं और खरीफ की बुवाई के लिए उर्वरकों की पूरी व्यवस्था है। देश में यूरिया के 6 प्लांट लगाए गए हैं, जो 76 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन कर रहे हैं। किसानों को 22 लाख सोलर पंप दिए गए हैं। देश में बिजली उत्पादन की पर्याप्त मात्रा है और 1500 मेगावाट पनबिजली जोड़ी जा रही है। वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर 250 गीगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। मानवीय स्तर पर देखें, तो ईरान युद्ध शुरू होने के बाद 3.75 लाख भारतीयों को वापस लाए हैं। ईरान से भी करीब 1000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। मेडिकल के 700 छात्रों को भी वापस लाने में हम सफल रहे हैं। भारतीय दूतावास 24 घंटे काम कर रहे हैं और भारतीयों के संपर्क में हैं। बहरहाल यह संसद में प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य का सारांश है। यह उनका दायित्व भी था कि देश को यथार्थ बताएं। इसे हम 'राष्ट्र के नाम संबोधन' ही नहीं, बल्कि वैश्विक संदेश मानते हैं। प्रधानमंत्री ने बार-बार मानवता की रक्षा और उसके हित में तनाव, युद्ध को अविलंब खत्म करने की अपील की है। भारत संयम, संवाद, शांति, स्थिरता और कूटनीति का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री के वक्तव्य के दो-अढाई घंटे बाद ही अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने, अचानक ही, एकतरफा और पांच दिनों का युद्धविराम घोषित कर दिया। उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत सार्थक और सकारात्मक रही है। ईरान अमरीका के साथ डील करना चाहता है। कैसी डील...! अमरीका ने तो ईरान के पॉवर प्लांट तबाह करने के लिए 48 घंटे की धमकी दी थी, लेकिन 12 घंटे शेष रहते ही युद्धविराम का ऐलान कर दिया। क्या यह ट्रंप का नया छलावा, षड्यंत्र है अथवा वह युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं? राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अब ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा।

श्रीराम और तीर्थंकर महावीर के बीच वंश परंपरा का मधुर संबंध

श्रमण डॉ पुष्पेन्द्र

चैत्र महीने का सीधा संबंध महापुरुषों के जन्मों के साथ जुड़ा हुआ है। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जन्मोत्सव आता है तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक (जन्म जयंती) भी चैत्र महीने में ही शुक्ल की त्रयोदशी को मनाया जाता है।

इन दो महान व्यक्तित्वों का जन्म चैत्र माह में ही सिर्फ 4 तिथियों के अंतर पर हुआ। हालांकि दोनों के जन्म में हजारों वर्षों का अंतर है। फिर भी दोनों के बीच एक मधुर, गहरा और अद्भुत संबंध है।

भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। इस महान परंपरा की तीर्थंकर परंपरा के प्रथमेश असि, मसि कृषि व अंक शब्दों के जनक प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ (ऋषभदेव) से हुआ, जो कि पहले तीर्थंकर थे। भगवान आदिनाथ अयोध्या के राजा नाभि के पुत्र के रूप में जन्मे। यानी अयोध्या न केवल श्रीराम की जन्मभूमि रही है, बल्कि जैन परंपरा में भी अत्यंत पवित्र स्थान है, क्योंकि यहां चार अन्य तीर्थंकरों का जन्म भी हुआ अजितनाथ (दूसरे), अभिनंदननाथ (चौथे), सुमतिनाथ (पांचवें) और अनंतनाथ (14वें)।

संयोग से, भगवान आदिनाथ का जन्म भी चैत्र मास में ही हुआ था। हालांकि वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। उन्होंने सूर्यवंश की इक्ष्वाकु परंपरा की स्थापना की, वही वंश जिसमें कई पीढ़ियों बाद भगवान श्रीराम का जन्म हुआ। इस सदी के चौबीस तीर्थंकरो में से तीन तीर्थंकरों, वासु पूज्य स्वामी, मुनि सुव्रतनाथ व नेमिनाथ तीर्थंकर को छोड़कर बाक़ी इक्कीस तीर्थंकर इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न हुए। इस प्रकार, भगवान महावीर की जैन परंपरा और भगवान श्रीराम की वंशावली दोनों की जड़ें भगवान आदिनाथ से जुड़ती हैं।

त्रिशष्टिशलाका पुरुषचरियं, पउम चरियं, पद्मपुराण साहित्यक ग्रंथों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उल्लेख सम्मिलित है। चौथे आरे के बीसवें तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी के समय में श्रीराम का उल्लेख मिलता है। जैन साहित्य अनुसार श्रीराम को बलदेव माना गया है जो कि 63श्लाघ्य पुरुष में आते हैं, तो एक दार्शनिक परंपरा है, दूसरी जैविक। यह संबंध केवल भूगोल, वंश और नामों तक सीमित नहीं है। यह गहराई तक विचार और मूल्य व्यवस्था में रचा-बसा है। चाहे तीर्थंकर हों या श्रीराम, सभी ने धर्म की भावना को जीवन का मूल बनाया। इक्ष्वाकु वंश का नाम ही इक्षु अर्थात गन्ने से लिया गया है। सरयू नदी के तट पर बसे अयोध्यावासी गन्ने की खेती करते थे थे और उसका रस निकालना जानते थे। यह बात तब और स्पष्ट हो जाती है जब हम पाते हैं कि भगवान ऋषभदेव ने अपने पौत्र श्रेयांस कुमार के हाथों हस्तिनापुर शहर में अपने 400 दिवसीय उपवास को अक्षय तृतीया के दिन गन्ने के रस को स्वीकार कर उस कठिन तपस्या का पारणा संपन्न किया।

विस्तृत गहराई से अगर अध्ययन किया जाए तो दोनों महापुरुषों ने सत्य, धर्म व सात्विक जीवन शैली तथा पर पीड़ा नहीं पहुँचाने का प्रयास ही नहीं किया अपितु जनमानस को संदेश भी दिया।

अनेक प्रकार से देखा और समझा जा सकता है कि मूलतः धर्म की आत्मा हमें यह सिखाती है कि मानव जीवन एक-दूसरे से गहराई से जुड़ा है। चाहे वो तीर्थंकर हों या मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम। धर्म वह स्वभाव है जो हर मानव के भीतर प्राकृतिक रूप से निहित है।

तीर्थंकर वर्द्धमान महावीर ने वर्तमान समय में व्यथित व कुंठित जनमानस को संदेश देते हुए कहा कि सर्व प्रथम मन पर नियंत्रण बनाना होगा। मन हमेशा दुख देता है। मन की इच्छाएँ अनंत हैं, वह कभी भी पूर्ण नहीं होता है। अगर एक इच्छा पूरी होगी तो उसके साथ सौ नई इच्छाएँ शुरू हो जाएँगी। ऐसे में सभी इच्छाएँ पूरी होंगी, इसकी कल्पना भी संभव नहीं है। जैसे ही इच्छा अपूर्ण हुई, मन विचलित होगा और दुख देगा। यही दुख और दूसरी इच्छाओं के अपूर्ण होने पर बढ़ता जाएगा। एक समय यह आएगा कि अनंत इच्छाओं की अपूर्णता लिए मन दुखों का अंबार उडेल देगा और पूरा जीवन दुखों के भंवर में उलझ जाएगा। बेहतर यही है कि मन पर नियंत्रण बनाओ और उसके साथ जीवन की इच्छाओं पर भी। अगर हम यह करने में सफल रहे तो गृहस्थ में रहकर भी मुक्ति का मार्ग पकड़ लेंगे। हम अनंत इच्छाओं के समुद्र में रहकर भी शांत और सुखी रहेंगे।

सुविधा, सुरक्षा और गति के नए युग की ओर बढ़ता भारत का भारतीयरेल भारत की जीवनरेखा कही जाने वाली भारतीय रेल आज एक ऐसे परिवर्तनकाल से गुजर रही है, जहाँ उसकी भूमिका केवल परिवहन तक सीमित नहीं रह गई है ।यह अब देश की आर्थिक गति, सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक एकात्मता का सशक्त माध्यम बन चुकी है ।वर्ष के प्रारम्भ में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा व्यक्त दृष्टि ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय रेल को पारंपरिक ढांचे से निकालकर आधुनिक, कुशल और यात्री-केंद्रित प्रणाली में रूपांतरित करना अब प्राथमिकता है ।यह परिवर्तन केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि धरातल पर तेजी से आकार लेता दिखाई दे रहा है।

भारतीय रेल में रिफॉर्म की पटरी पर विकास का बिगुल

बिनोद कुमार सिंह

रेल भवन में आयोजित हालिया प्रेस वार्ता में घोषित आठ प्रमुख सुधारों ने इस बदलाव को एक स्पष्ट दिशा दी है। ये सुधार किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं,बल्कि रेलवे के संचालन,संरचना,सेवा और सोच–सभी को समाहित करते हैं।यही कारण है कि आज भारतीय रेल का चेहरा व्यापक रूप से बदलता नजर आ रहा है।आधुनिक ट्रेनों के संचालन ने इस परिवर्तन को सबसे अधिक दृश्य रूप दिया है।अमृत भारत,वंदे भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत स्लीपर जैसी ट्रेनों ने यात्रा के अनुभव को नई ऊँचाई दी है।ये ट्रेनें गति,आराम और तकनीकी उत्कृष्टता का संतुलित मेल प्रस्तुत करती हैं।वही नमो भारत ट्रेन क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई गति देते हुए छोटे शहरों और महानगरों के बीच दूरी को कम कर रही है।इसके साथ ही बुलेट ट्रेन परियोजना भारत को उच्च गति रेल नेटवर्क की वैश्विक श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी प्रयास है।स्टेशनों का पुनर्विकास इस परिवर्तन की दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी है।देश के अनेक रेलवे स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होकर यात्रियों को एक व्यवस्थित,स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण प्रदान कर रहे हैं। प्रतीक्षालयों की गुणवत्ता,डिजिटल सूचना प्रणाली,एस्केलेटर और लिफ्ट जैसी सुविधाएँ अब सामान्य होती जा रही हैं। रेलवे स्टेशन अब केवल यात्रा के पड़ाव नहीं,बल्कि अनुभव के केंद्र बनते जा रहे हैं।इन व्यापक परिवर्तनों के बीच घोषित आठ सुधार भारतीय रेल के भविष्य की बुनियाद के रूप में उभरते हैं।सबसे पहला सुधार टिकटिंग प्रणाली के पूर्ण डिजिटली करण और सरलीकरण से संबंधित है।टिकट बुकिंग की जटिलताओं को समाप्त कर इसे पारदर्शी और सहज बनाने का प्रयास किया जा रहा है।मोबाइल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जा रहा है,जिससे हर वर्ग का यात्री बिना किसी कठिनाई के टिकट प्राप्त कर सके।दूसरा सुधार सुरक्षा तंत्र के सुदृढ़ीकरण का है।रेलवे परिसरों और ट्रेनों में आधुनिक निगरानी प्रणाली, सीसीटीवी नेटवर्क और तकनीक आधारित सुरक्षा उपायों को विस्तार दिया जा रहा है।इससे यात्रियों में सुरक्षा का विश्वास बढ़ेगा और रेलवे एक अधिक सुरक्षित यात्रा माध्यम के रूप में स्थापित होगा।तीसरा सुधार समय बद्धता और परिचालन दक्षता पर केंद्रित है।ट्रेनों की देरी को कम करने के लिए सिग्नलिंग प्रणाली का आधुनिकी करण,ट्रैक उन्नयन और बेहतर संचालन प्रबंधन पर बल दिया जा रहा है।यह पहल रेलवे की विश्वसनीयता को मजबूत करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।

चौथा सुधार स्टेशनों के कायाकल्प से जुड़ा है,जिसके अंतर्गत उन्हें आधुनिक सुविधाओं और बेहतर प्रबंधन के साथ विकसित किया जा रहा है।इससे यात्रियों को एक सुव्यवस्थित और सम्मानजनक यात्रा अनुभव प्राप्त होगा।

पाँचवाँ सुधार खानपान और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने का है।भोजन की गुणवत्ता और सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त निगरानी तंत्र विकसित किया जा रहा है,जिससे यात्रियों को सुरक्षित और संतोषजनक सेवाएँ मिल सकें।

छठा सुधार आधुनिक ट्रेनों के विस्तार और उनकी गति में वृद्धि का है।नई पीढ़ी की ट्रेनों के माध्यम से यात्रा को तेज,आरामदायक और तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जा रहा है,जिससे भारतीय रेल वैश्विक मानकों की ओर अग्रसर हो सके।

सातवाँ सुधार बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और हाई-स्पीड परियोजनाओं के विकास से संबंधित है।ट्रैक,पुल और अन्य संरचनाओं के उन्नयन के साथ-साथ बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाएँ रेलवे को नई ऊँचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखती हैं।आठवाँ और अंतिम सुधार पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का है।रेलवे तेजी से विद्युतीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है,जिससे डीजल पर निर्भरता कम हो और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखा जा सके।यह कदम सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

इन सुधारों की श्रंखला में भारतीय रेल केवल अपनी संरचना ही नहीं, बल्कि अपनी कार्यशैली और दृष्टिकोण को भी बदल रही है।अब यह एक ऐसी सेवा प्रणाली के रूप में उभर रही है,जो यात्रियों की अपेक्षाओं को समझते हुए उन्हें प्राथमिकता देती है।यह परिवर्तन देश की अर्थव्यवस्था को गति देने, व्यापार को सशक्त करने और दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

आज भारतीय रेल जिस दिशा में आगे बढ़ रही है,वह एक नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करती है -जहाँ गति है,सुरक्षा है,सुविधा है और सबसे बढ़कर विश्वास है।यह विकास का बिगुल केवल पटरियों तक सीमित नहीं,बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति

पुलिस तंत्र में मुखबिर असुरक्षित? लीक होती गोपनीय सूचनाओं से उठे गंभीर सवाल

संदीप द्विवेदी

संपादक दैनिक मीडिया ऑडीटर

पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। खासकर मुखबिर तंत्र की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आ रही हैं। जिन सूचनाओं को अत्यंत गोपनीय रखा जाना चाहिए वही अब सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप ग्रुप्स में खुलेआम वायरल हो रही हैं। इससे न सिर्फ विभागीय गोपनीयता पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है बल्कि उन मुखबिरों की जान भी खतरे में पड़ रही है जो अपनी पहचान छिपाकर पुलिस की मदद करते हैं। सूत्रों की मानें तो कई मामलों में थाना स्तर से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों एसपी और आईजी स्तर तक की गोपनीय चर्चाएं भी सार्वजनिक हो जाती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विभाग के भीतर ही कहीं न कहीं लापरवाही या मिलीभगत हो रही है? अगर संवेदनशील जानकारी अंदरखाने ही बाहर पहुंचाई जा रही है तो यह न केवल अनुशासनहीनता है बल्कि पूरे सुरक्षा तंत्र के लिए बड़ा खतरा भी है। मुखबिर किसी भी पुलिस व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। अपराधियों तक पहुंचने बड़े नेटवर्क का खुलासा करने और समय रहते कार्रवाई करने में उनकी भूमिका अहम होती है। लेकिन जब यही मुखबिर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगें तो यह स्थिति बेहद चिंताजनक हो जाती है। कई मामलों में देखा गया है कि जानकारी लीक होने के बाद अपराधी सतर्क हो जाते हैं और मुखबिरों की पहचान उजागर होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे उनके ऊपर हमले या सामाजिक बहिष्कार जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं।

विडंबना यह है कि एक ओर अधिकारी एसी कमरों में बैठकर सफलता की कहानियां गढ़ते हैं वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर काम करने वाले मुखबिरों को उचित सुरक्षा और सम्मान नहीं मिल पाता। कई मुखबिर अब पुलिस से दूरी बनाने लगे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनकी पहचान उजागर न हो जाए। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में पुलिस को खुफिया सूचनाओं के लिए गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल युग में सूचना का प्रवाह तेज हुआ है लेकिन इसके साथ ही गोपनीयता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी हो गया है। विभाग को चाहिए कि वह आंतरिक निगरानी तंत्र को मजबूत करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी संवेदनशील जानकारी बिना अनुमति के बाहर न जाए। साथ ही जो कर्मचारी इस तरह की लापरवाही या जानबूझकर लीक करने में शामिल पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस विभाग इस गंभीर मुद्दे को समय रहते समझेगा या फिर मुखबिर तंत्र के कमजोर होने का खामियाजा पूरे कानून-व्यवस्था को भुगतना पड़ेगा? अगर हालात नहीं सुधरे तो वह दिन दूर नहीं जब मुखबिर पूरी तरह से किनारा कर लेंगे और पुलिस का सबसे मजबूत हथियार खुद ही कमजोर पड़ जाएगा।

ऊर्जा ठिकानों पर हमले: दुनिया को मंदी की ओर धकेलता युद्ध

ईरान के साऊथ पार्स गैस फील्ड पर इजरायली हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर यह हमला केवल एक सैन्य घटना नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा प्रहार है। आपूर्ति में रुकावट के कारण कई देशों को लंबे समय तक ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ सकता है। द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार अंतराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इतिहास का सबसे खराब वैश्विक ऊर्जा व्यवधान बताया है, जो 1973 के अरब तेल प्रतिबंध को भी पीछे छोड़ दिया है।

राज कुमार सिन्हा

मुख्य निवेश अधिकारी डैन पिकरिंग ने कहा कि आप ऊर्जा संरक्षण के जरिए इस समस्या से बच नहीं सकते। इसका नतीजा यह होगा कि कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि लोग उपभोग करना बंद कर देंगें। यह पहली बार है जब खाड़ी क्षेत्र में ईरान के ऊर्जा ढांचे को सीधे निशाना बनाया गया है। 17 मार्च तक, अमेरिका और इज़राइल ने खाड़ी में ईरान के ऊर्जा उत्पादन केंद्रों को निशाना बनाने से परहेज किया था। यहां तक कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के 90 प्रतिशत तेल निर्यात के केंद्र खारग द्वीप पर हमला किया, तब भी केवल सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया गया था। इजराइल द्वारा कतर के साथ साझा किए जाने वाले साऊथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमले के बाद यह स्थिति बदल गई है। पार्स गैस फील्ड दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का हिस्सा है, जिसे ईरान कतर के साथ साझा करता है। इस घटना को अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे युद्ध को बड़े ऊर्जा संकट के रूप में देखा जा रहा है। जवाब में ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और कतर के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया।

ईरान ने सऊदी अरब में तेल कंपनी अरामको की रिफाइनरी के साथ-साथ कतर और यूएई में गैस सुविधाओं पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। यह युद्ध का एक खतरनाक मोड़ साबित हो रहा है। साउथ पार्स गैस क्षेत्र, भारत सहित वैश्विक एलएनजी आपूर्ति की रीढ़ है। इजरायली हमले के बाद तेल और गैस की कीमतों में आई तत्काल वृद्धि से इसके महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाने के कारण दुनिया पहले से ही कच्चे तेल की आपूर्ति में व्यवधान से जूझ रही है। ऐसे में उत्पादन सुविधाओं को होने वाली किसी भी क्षति का प्रभाव वर्षों तक बना रह सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य में चल रही बाधाओं ने यह दिखा दिया है कि एक छोटा समुद्री मार्ग भी वैश्विक सप्लाई चेन को हिला सकता है। कतर के रास लाफान औद्योगिक शहर, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यात केंद्र है, ईरानी मिसाइल हमलों से तबाह हो गया है। रास लाफान पर हमलों के कारण कतर की कुल एलएनजी निर्यात क्षमता में लगभग 17 प्रतिशत की कमी आई है। कतर एनर्जी के अधिकारियों के अनुसार, इस नुकसान की मरम्मत में 3 से 5 साल का समय लग सकता है, जिससे यह एक

दीर्घकालिक संकट बन गया है। इस हमले से कतर को प्रति वर्ष लगभग 20 अरब डॉलर के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है।

यह हमला केवल कतर तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। भारत अपनी प्राकृतिक गैस जरूरतों का लगभग 40 से 50 प्रतिशत कतर से आयात करता है, इसलिए यह स्थिति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। मध्य पूर्व से चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को तेल का लगभग 75 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस का 59 प्रतिशत निर्यात होता है।

इन सभी अर्थव्यवस्थाओं को तेल-गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन और उत्पादन जैसे कई क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने कहा है कि खाद्य सेवा उद्योग का 75 फिसदी हिस्सा एलपीजी पर निर्भर है और लंबे समय तक इसकी कमी रहने से अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन 12 से 13 हजार करोड़ रुपए नुकसान हो सकता है। युद्ध के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 39 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई हैं। ईंधन और प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतों से दुनिया भर में माल ढुलाई और उत्पादन लागत बढ़ गई है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। भारत में भी प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए और इंडस्ट्रियल डिजल 22 रुपए प्रति लीटर महंगी हो गई है। दुनिया भर में यूरिया की कुल आपूर्ति में कतर का लगभग 10 प्रतिशत योगदान है। लेकिन ईरानी हमले की वजह से कतर के कई प्लांट बंद हैं, जिससे भारत में भी खाद की किल्लत बढ़ सकती है।

यदि यह संघर्ष लंबा चलता है, तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल सकता है। ऊर्जा और खाद्य कीमतों में वृद्धि ने वैश्विक मुद्रास्फीति को बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर के अनुमान घटाए हैं। विकासशील देशों में पूंजी प्रवाह कम हुआ है। कई देशों ने अपने रक्षा बजट बढ़ा दिए हैं, जिससे सामाजिक और विकासात्मक खर्चों पर दबाव बढ़ा है। भारत सहित वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई है। भारतीय शेयर बाजार में पिछले तीन सप्ताह में 27 से 34 लाख करोड़ रुपये तक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पूंजी निकाल रहे हैं। मूडीज के अनुसार, ऊर्जा की कीमतें बढ़ती रहीं तो भारतीय रुपये पर दबाव और बढ़ेगा। खाडी देशों में 90 लाख भारतीय काम कर रहे हैं। युद्ध के कारण 50 हजार भारतीय वापस देश लौट चुके हैं। अगर युद्ध लंबा खिंच गया तो काम प्रभावित होगा और शेष भारतीय भी वापस लौटने को मजबूर होंगे। खाडी देशों में भारतीय काम करके अच्छा खासा रेमिटेंस भारत में भेजते हैं। जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि यदि संघर्ष जारी रहता है, तो कतर और कुवैत की जीडीपी में 14 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है। यह विदित है कि युद्ध के कारण अनिश्चितता बढ़ती है, जिससे निजी निवेश रुक जाता है और वित्तीय प्रणाली कमजोर होती है। युद्ध राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, बुनियादी ढांचे के विनाश और दीर्घकालिक आर्थिक विकास में गिरावट का कारण बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुए 100 से अधिक युद्धों के अध्ययन में यह पाया गया कि इन संघर्षों के कारण संबंधित देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर गंभीर और दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़े। वर्तमान युद्धों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुआयामी संकट में डाल दिया है। यदि यह संघर्ष जल्द समाप्त नहीं होता, तो यह 1990 के बाद के सबसे बड़े आर्थिक संकटों में से एक बन सकता है। यह संकट दुनिया भर के उपभोक्ताओं, व्यवसायों और नीति निर्माताओं के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है और वैश्विक मंदी के जोखिम को बढ़ा रहा है।

(बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ) (यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

वीवीपैट एवं ईवीएम का त्रैमासिक भौतिक निरीक्षण संपन्न

राजनीतिक दलों की उपस्थिति में पारदर्शी प्रक्रिया, मशीनों की सुरक्षा व कार्यप्रणाली की हुई गहन जांच

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। 25 मार्च 2026: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार, बुधवार को जिले में वीवीपैट एवं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का त्रैमासिक भौतिक निरीक्षण किया गया यह निरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी के अनुरूप पूरी पारदर्शिता और सावधानी के साथ किया गया निरीक्षण के दौरान वीवीपैट एवं ईवीएम मशीनों की भौतिक स्थिति, सील की सुरक्षा, स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित भंडारण व्यवस्था, तथा तकनीकी कार्यप्रणाली का सूक्ष्म परीक्षण किया गया यह सुनिश्चित किया गया कि सभी मशीनें निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुरूप सुरक्षित और कार्यक्षम हैं निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह से निर्धारित

प्रोटोकॉल के तहत संपन्न की गई जिससे किसी भी प्रकार की त्रुटि या संदेह की संभावना न रहे निरीक्षण में कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की उपस्थिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया जिनमें भारतीय जनता पार्टी के आशिष सिंह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भावेश जैन, बहुजन समाज पार्टी के हरिशंकर, आम आदमी पार्टी के रमाशंकर मिश्रा, और जिला पंचायत सदस्य सुखमंती सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे निरीक्षण के उपरांत सभी प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने प्रक्रिया को संतोषजनक, पारदर्शी, और

निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बताया उन्होंने मशीनों की सुरक्षा, रखरखाव और निगरानी व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया जिला प्रशासन ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का नियमित निरीक्षण किया जाता है जिससे चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता को मजबूती मिलती है।

दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों का नवाचार में शानदार प्रदर्शन

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, मनेन्द्रगढ़ एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता और नवाचार के लिए चर्चा में है। विद्यालय के दो मेधावी विद्यार्थियों अक्षरा सिन्हा और रचित गुप्ता ने आयोजित नवाचार प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए क्रमश विमेन सेफ्टी डिवाइसेस एवं 'डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन आरसी बोट फॉर क्लीनिंग वाटर' विषयों पर 10,000-10,000 की प्रोत्साहन राशि प्राप्त की यह उपलब्धि विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच, परिश्रम और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सशक्त उदाहरण है। Department of Science & Technolog 4 द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में नवाचार की भावना को बढ़ावा देना और उनके विचारों को व्यवहारिक रूप देना है अक्षरा सिन्हा द्वारा तैयार 'विमेन सेफ्टी डिवाइसेस' परियोजना महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है जबकि रचित गुप्ता की 'आरसी बोट' परियोजना जल स्त्रोतों की सफाई के लिए एक उपयोगी तकनीकी समाधान प्रस्तुत करती है दोनों परियोजनाएं समाज की वास्तविक समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही हैं विद्यालय के प्राचार्य डॉ. बसंत कुमार तिवारी ने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान न केवल छात्रों के लिए बल्कि पूरे विद्यालय परिवार के लिए गर्व का विषय है।

ओलंपिक में एमसीबी का ऐतिहासिक प्रदर्शन, 8 स्वर्ण सहित 26 पदकों से गूंजा संभाग

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक में एमसीबी जिले के खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल से सबको प्रभावित किया 21 से 23 मार्च तक अंबिकापुर में आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में एमसीबी ने 8 स्वर्ण, 14 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 26 पदक जीतकर अपने जिले का नाम रोशन किया प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा किया गया इस दौरान अंतरराष्ट्रीय पहलवान गीता फोगाट की प्रेरक उपस्थिति ने खिलाड़ियों में जोश और आत्मविश्वास का संचार किया वहीं, समापन समारोह में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर भाइचुंग भूटिया ने आयोजन को गौरवशाली आयाम प्रदान किया एमसीबी के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में अपनी श्रेष्ठता साबित की। ट्रैक एंड फील्ड से लेकर कुश्ती, कराते और कबड्डी तक, हर क्षेत्र में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। 100 मीटर दौड़ में टी. होमेश्वर राव की तेज रफ्तार, भाला फेंक में कुमारी अनिता सिंह की सटीकता ऊंची कूद में आनंद कुमार की उड़ान कराते में कुमारी आराधना मार्को का जुझारूपन और कुश्ती में सीमा सिंह की ताकत ने स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया कबड्डी में भी एमसीबी का दबदबा था जहां जूनियर बालक, जूनियर बालिका और सीनियर बालक वर्ग की टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर टीम स्पिरिट और रणनीति का शानदार प्रदर्शन किया। कांस्य पदक में सुरेंद्र सिंह (कराते 67 किग्रा), शनि लुइश (कुश्ती 57 किग्रा), कंचन सिंह (ऊंची कूद), तथा तीरंदाजी में शिवम, मुकेश और चंदन ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। इस अभूतपूर्व सफलता पर एमसीबी जिले के कलेक्टर डी. वेंकट राहुल ने खिलाड़ियों को बधाई दी और इसे जिले की उभरती खेल प्रतिभाओं और मजबूत खेल संरचना का परिणाम बताया उन्होंने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। जिला खेल अधिकारी विनोद जायसवाल ने इसे 'जिले के लिए गौरवपूर्ण क्षण' बताते हुए कहा कि यह सफलता भविष्य में और बड़े खेल लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा बनेगी इस ऐतिहासिक जीत ने न केवल सरगुजा संभाग में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में जिले की पहचान को एक सशक्त खेल शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है।

केल्हारी की रेत खदान पर उठे सवालों का अंत जांच में मिली क्लीन चिट, वैध पास से हो रहा

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले के खनिज विभाग ने ग्राम पंचायत बिछियाटोला, तहसील केल्हारी स्थित रेत खदान की विस्तृत जांच की जिसके बाद यह स्पष्ट हुआ कि खदान संचालन में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई कलेक्टर (खनिज शाखा) कार्यालय के निर्देश पर 24 मार्च 2026 को खनिज विभाग के अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया जिसमें खदान क्षेत्र का बारीकी से अवलोकन किया गया निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि रेत उत्खनन का कार्य पर्यावरणीय नियमों और निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है खदान से रेत का परिवहन ट्रैक्टर के माध्यम से किया जा रहा था और इसमें वैध अभिवहन पास का उपयोग किया जा रहा था यह पुष्टि करता है कि खनन कार्य पूरी तरह से वैधानिक प्रक्रिया के तहत

संचालित है अधिकारियों ने रेत भंडारण स्थल का भी जायजा लिया जहां यह पाया गया कि रेत का भंडारण निर्धारित और स्वीकृत स्थल पर किया जा रहा है संबंधित भंडारण स्थल को विधिवत स्वीकृति मिली हुई है और उसकी अनुमति अवधि 16 जून 2023 से 15 जून 2026 तक प्रभावी है इसके अलावा जल एवं वायु संबंधी पर्यावरणीय स्वीकृति भी 30 जून 2027 तक मान्य है जो सभी आवश्यक नियमों के पालन को दर्शाता है जांच टीम ने मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से भी चर्चा की जिनके अनुसार खदान और भंडारण कार्य शुरू होने के बाद क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं इससे स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है और गांव में विकास की गति तेज हुई है इस पूरी जांच के बाद तैयार किए गए प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि खदान संचालन में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है और सभी कार्य निर्धारित नियमों एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुसार संचालित हो रहे हैं।

मल्टीलेवल पार्किंग को लेकर एमआईसी बैठक में भिड़े पार्षद

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (निप्र)। कलेक्टोरेट परिसर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मल्टीलेवल पार्किंग में आटोडील का कारोबार करने का आरोप है अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एमआईसी के सदस्यों ने मेयर को घेरा स्मार्ट सिटी के जीएम (रेवेन्यू) एवं नगर निगम के अपर आयुक्त खजांची कुम्हार ने बताया कि पार्किंग का ठेका राजन जायसवाल को तीन वर्षों के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्किंग में ऑटोडील का धंधा होने पर उसे तत्काल रोकने और पार्किंग का उपयोग केवल गाड़ियों के पार्किंग के लिए करने के निर्देश दिए गए है अपर आयुक्त के अनुसार इस मामले की जांच का जिम्मा जोन 3 को सौंपा गया है। हालांकि जोन 3 के प्रभारी जोन कमिश्नर प्रवीण शुक्ला ने बताया कि शाम पौने छह बजे तक उन्हें जांच संबंधी कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है स्मार्ट सिटी के जीएम (टेक्निकल) एसपी साहू ने कहा कि ठेकेदार को नोटिस भेजने की बात कही जा रही है लेकिन यह आदेश कब और किसने जारी किया, इसकी प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप का कहना है कि जनता के उपयोग के लिए बनाई गई मल्टीलेवल पार्किंग का शतप्रतिशत उपयोग वाहनों की पार्किंग के लिए होना चाहिए वहां कोई धंधा कैसे कर सकता है उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करना चाहिए।

नल से जल ने बदली तकदीर : बब्बी बाई के जीवन में आया खुशियों का सवेरा

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहनटोला की बब्बी बाई की कहानी आज पूरे गांव में बदलाव की प्रेरणा बन चुकी है पहले जहां हर दिन बब्बी बाई को पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी वहीं अब उनके जीवन में सुख और सुविधा का दौर आया है पहले बब्बी बाई का हर दिन कुएं और हैंडपंप से पानी लाने की जद्दोजहद में गुजरता था। सुबह होते ही पानी की चिंता शुरू हो जाती थी और इस काम में न केवल समय खर्च होता था बल्कि शारीरिक श्रम भी अधिक करना पड़ता था स्वच्छ पानी की कमी के कारण अक्सर स्वास्थ्य समस्याएं भी होती थीं लेकिन अब 'हर घर नल से जल' योजना ने उनकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया है अब उनके घर में लगे नल से साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध है जिससे न सिर्फ

उनका समय बचा है बल्कि जीवन में सहजता और खुशहाली भी आई है अब वे अपने परिवार और अन्य कार्यों के लिए ज्यादा समय दे पा रही हैं बब्बी बाई की आंखों में चमक और चेहरे पर सुकून साफ नजर आता है, जब वे कहती हैं 'अब पानी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता हमारे घर में ही शुद्ध पानी मिल रहा है यह योजना हमारे गांव के लिए वरदान साबित हुई है और हमारे बच्चों का भविष्य भी बेहतर हो रहा है इस सुविधा के लिए बब्बी बाई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करती हैं उनका कहना है 'यह पहल सच में ग्रामीण जीवन को नई दिशा देने वाली है। बब्बी बाई की यह कहानी सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि उस बदलते भारत की तस्वीर है जहां सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन को सरल, सुरक्षित और सम्मानजनक बना रही हैं 'हर घर नल से जल' योजना ने न केवल बब्बी बाई के जीवन को बेहतर बनाया है बल्कि पूरे गांव में बदलाव की एक नई लहर भी पैदा की है।

एमसीबी जिले से टीबी मुक्त भारत अभियान का स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया ऐतिहासिक शुभारंभ

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। विश्व क्षय दिवस के अवसर पर जिले में 'टीबी मुक्त भारत अभियान' के तहत 100 दिवसीय विशेष अभियान का भव्य शुभारंभ हुआ इस अभियान की राष्ट्रीय शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा द्वारा नोएडा से वर्चुअल रूप से की गई जबकि छत्तीसगढ़ में इसका राज्य स्तरीय शुभारंभ जिले से होना ऐतिहासिक साबित हुआ कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने अभियान की विस्तृत जानकारी दी उन्होंने बताया कि देश टीबी उन्मूलन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह 100 दिवसीय अभियान उसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कार्यक्रम के दौरान कहा '24

मार्च का दिन ऐतिहासिक महत्व रखता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टीबी मुक्त भारत का संकल्प तेजी से साकार हो रहा है उन्होंने यह भी बताया कि 7 दिसंबर 2024 से 24 मार्च 2025 तक चले अभियान में 4113 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। जिले की 118 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को गांधी जी की प्रतिमा और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया अभियान की प्रमुख विशेषता यह है कि अब स्वास्थ्य सेवाएं गांव-गांव तक पहुंचेंगी आयुष्मान स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लोगों की जांच की जाएगी जिसमें रक्त जांच के साथ हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन से छाती का एक्स-रे किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मदद से केवल 5 से 10 मिनट में रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी जिससे शुरुआती स्तर पर टीबी की पहचान संभव होगी इस समय जिले में 203 टीबी मरीज उपचाररत हैं जिनमें 7 एमडीआर और 4 टीबी संक्रमण के मरीज शामिल हैं सभी मरीजों को निक्षय पोषण योजना के तहत 1000 रुपये प्रतिमाह (6 माह तक) तथा राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 200 रुपये प्रतिमाह की सहायता मिल रही है अभियान को चार चरणों में संचालित किया जाएगा पहले चरण में घर-घर सर्वे कर संभावित मरीजों की पहचान की जाएगी इसके बाद विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा कार्यक्रम के अंत में स्वास्थ्य मंत्री ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जो जिलेभर में अभियान का प्रचार-प्रसार करेगा कार्यक्रम में चंपा देवी पावले, महापौर रामनरेश राय, सभापति संतोष सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह और अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। अंत में सभी ने एक स्वर में संकल्प लिया कि 'हम सब ने ठाना है।

2021 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को देनी होगी जॉइनिंग, सुप्रीम कोर्ट बोला- जांच के नाम पर नहीं रोक सकते नियुक्ति, के आदेश को सही ठहराया

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (निप्र)। 2021 में चयनित उम्मीदवारों को अब राज्य सरकार को जॉइनिंग देनी होगी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दी है सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है दरअसल 2021 में गड़बड़ी सामने आने के बाद राज्य शासन ने सीबीआई जांच की घोषणा की थी सीबीआई इस केस की जांच कर रही है जबकि एग्जाम में सिलेक्टेड

उम्ममीदवारों को राज्य शासन ने जांच का हवाला देकर नियुक्ति आदेश नहीं दिया है इससे परेशान होकर डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के पद पर चयनित उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा कि उनका चयन मेरिट पर हुआ है न तो उनके खिलाफ कोई जांच चल रही है और न ही कोई केस दर्ज है इसके बाद भी उन्हें जॉइनिंग से रोक दिया गया है हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति

रोकने का कारण पूछा था जवाब में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच का हवाला दिया था जिससे असंतुष्ट हाईकोर्ट ने चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल पिटिशन लीव दायर कर चुनौती दी।

शिक्षा मंत्री ने जारी किया 5वीं-8वीं का रिजल्ट टॉप-10 से बाहर शिवपुरी

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने वल्लभ भवन में एक कार्यक्रम में बटन दबाकर परिणाम जारी किए इस बार प्रदेश में 5वीं का उत्तीर्ण प्रतिशत 95.14% और 8वीं का 93.83% रहा हालांकि शिवपुरी जिला दोनों कक्षाओं में प्रदेश के टॉप-10 जिलों से बाहर रहा प्रदेश स्तर पर जारी इन परिणामों में छात्राओं ने छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है कक्षा 8वीं के परिणाम में शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का गृह जिला नरसिंहपुर प्रदेश में पहले स्थान पर रहा जिले के प्रदर्शन की बात करें तो कक्षा 5वीं में जिले का प्रदर्शन औसत से बेहतर रहा यहां कुल 37,755 छात्र परीक्षा में शामिल हुए जिनमें से 36,614 छात्र उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार जिले का उत्तीर्ण प्रतिशत 96.98% दर्ज किया गया और इसे प्रदेश में 16वां स्थान मिला वहीं कक्षा 8वीं में जिले का प्रदर्शन कमजोर रहा इस कक्षा में कुल 30,287 छात्र परीक्षा में बैठे जिनमें से 28,411 छात्र सफल हुए जिले का उत्तीर्ण प्रतिशत 93.81% रहा और इसे प्रदेश में 32वां स्थान प्राप्त हुआ जिसके कारण शिवपुरी टॉप-10 जिलों की सूची से बाहर रहा प्रदेश स्तर पर जहां 5वीं में 95.14% और 8वीं में 93.83% छात्र पास हुए हैं।

अफवाहों से आगर मालवा में पेट्रोल पंपों पर भीड़ कुछ पंपों पर स्टॉक खत्म, कानड़ में मारपीट

मीडिया ऑडीटर, आगर मालवा (निप्र)। आगर मालवा जिले में अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच तनाव की अफवाहों के कारण ईंधन संकट की आशंका गहरा गई है। मंगलवार देर रात से ही पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी, जो बुधवार दोपहर तक जारी रही। जिला मुख्यालय स्थित गुप्ता पेट्रोल पंप पर मंगलवार देर रात भारी भीड़ के कारण पेट्रोल खत्म हो गया था। इसके चलते पंप को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। पंप संचालक नवीन गुप्ता ने बताया कि बुधवार सुबह टैंकर पहुंचने के बाद लगभग 9 बजे से पेट्रोल-डीजल का वितरण फिर से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अब पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और अन्य टैंकर भी आने वाले हैं। मार्केटिंग सोसायटी पेट्रोल पंप पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुबह कुछ समय के लिए मशीनें बंद रखी गईं। पंप मैनेजर ईश्वर यादव के अनुसार, यहां लगभग 30-30 हजार लीटर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक मौजूद है और सुबह 9 बजे से वितरण शुरू कर दिया गया था। जिले के कुछ अन्य पेट्रोल पंपों, जिनमें नायरा, ताज फीलिंग स्टेशन, ढाबला पिपलोन और ग्राम कुबड़िया खेड़ी शामिल हैं, पर भी रिजर्व स्टॉक के अलावा पेट्रोल खत्म होने की सूचना मिली है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी एम.एल. मालवीय ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 57 पेट्रोल पंप हैं और सभी स्थानों से लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। एम.एल. मालवीय ने स्पष्ट किया कि जिले में ईंधन की कुल मि ाकर कोई कमी नहीं है। उनके अनुसार, कुछ पंपों पर पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है, और कुछ स्थानों पर तो दो माह तक का भंडारण भी मौजूद है। इस बीच, कानड़ में मंगलवार रात एक पेट्रोल पंप पर पहले पेट्रोल भरवाने को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद जल्द ही मारपीट में बदल गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, वहां मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराया। इस घटना का वीडियो बुधवार सुबह सामने आया। कुल मिलाकर, आगर जिले में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति फिलहाल सुचारू बनी हुई है।

बैतूल में बोलेरो पलटी, बाइक सवार महिला-बच्चा घायल रानीपुर रोड पर अनियंत्रित होकर हुआ हादसा

मीडिया ऑडीटर, बैतूल (निप्र)। बैतूल के रानीपुर रोड पर बुधवार को एक तेज रफ्तार बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में बाइक सवार एक महिला और एक बच्चा घायल हो गए, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार, दुर्घटना बैतूल-सारणी स्टेट हाईवे पर कमानी गेट से आगे पेट्रोल पंप के पास हुई। बोलेरो वाहन (क्रमांक स्क्र48 क्ष्ट 2902) अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया और इस दौरान एक बाइक को टक्कर मार दी।

बोलेरो पर वन सुरक्षा की लगी है प्लेट: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पेट्रोल पंप के सामने अचानक ब्रेक लगाने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे हादसा हुआ। बोलेरो में तीन युवक सवार थे, जो हनुमान डोल से लौट रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने चालक जीतू परते को हिरासत में लेकर कोतवाली थाने पहुंचाया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि वाहन पर 'वन सुरक्षा, मध्यप्रदेश शासन' की प्लेट लगी हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

कार्रवाई : 25 किलो डोडाचूरा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

मीडिया ऑडीटर, रायसेन (निप्र)। जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गौहरगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को 25 किलो 900 ग्राम अवैध डोडाचूरा के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 60 हजार रुपए बताई जा रही है। 23 मार्च को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो युवक तारानगर ओवरब्रिज के पास बैग में डोडाचूरा रखकर बिक्री के लिए खड़े हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विनोद परमार के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान बैग में पन्नी में छिपाकर रखा गया डोडाचूरा बरामद हुआ, जिसे जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में अजय पिता किशोरसिंह रायसिख (30) और ब्रजेश पिता दलवीरसिंह रायसिख (19) निवासी ग्राम रमगड़ा, थाना बाड़ी शामिल हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है।

विश्व क्षय दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन

मीडिया ऑडीटर, राजगढ़ (निप्र)। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत मंगलवार को विश्व क्षय दिवस के अवसर पर शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय राजगढ़ में क्षय दिवस कार्यक्रम की कार्यशाला मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शोभा पटेल के मार्गदर्शन में किया गया। जिसमें टीबी कार्यक्रम के बारे में विस्तार जानकारी दी गई। टीबी मरीजों की टेस्टिंग, उपचार, निदान, निक्षय पोषण योजना , फूडबास्केट, निक्षय मित्र आदि के बारें में बताया गया। उन्?होंने बताया कि म.प्र. में राजगढ़ का टीबी सक्सेस रेट 94 प्रतिशत है, जो कि मध्यप्रदेश में सर्वोच्च जिलों में आता है। जिन संभावित टीबी मरीजों को 10 लक्षणों में से (खांसी या कफ दो हफ्ते से ज्यादा बुखार, रात में पसीना आना, बलगम में खून आना, सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत होना, वज़न का कम होना, भूख न लगना, थकान, लक्षण होने पर हाईटेक नॉट मशीन द्वारा टेस्ट किया जाता है।

इटारसी में पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाहों से लगी भीड़

मीडिया ऑडीटर, इटारसी (निप्र)। इटारसी में बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाह फैलते ही शहर के पेट्रोल पंपों पर भीड़ पहुंच रही है। बुधवार को रेलवे स्टेशन के सामने स्थित भारत पेट्रोलियम के पंप पर सुबह से ही दोपहिया और चारपहिया वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

कतारों से सड़क पर बढ़ा दबाव : भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ समय के लिए आसपास के रास्तों पर यातायात भी प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को अपनी बारी के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। अफवाह के कारण लोग जल्दी-जल्दी टंकी फुल कराने के लिए पंपों पर पहुंच रहे थे। पंप कर्मचारियों के समझाने के बावजूद दिनभर भीड़ कम नहीं हुई। शहर के न्यास कॉलोनी स्थित पेट्रोल पंप और सिटी थाने के सामने वाले पंप सहित अन्य जगहों पर भी इसी तरह के हालात देखे गए।

पंप कर्मचारियों ने कहा- हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है : पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने साफ किया कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। उनके अनुसार, पंप पर पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और शाम तक एक और टैंकर आने की संभावना है। पंप की एक महिला मैनेजर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि लोगों में कमी को लेकर गलत धारणा फैल गई है, जबकि ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब कर्मचारियों ने लोगों से अपील की है कि वे जरूरत के हिसाब से ही पेट्रोल-डीजल भरवाएं।

गर्मी बढ़ी तो मटका-सुराही की मांग तेज, बिक्री तीन गुना

मीडिया ऑडीटर, अकोदिया (निप्र)। गर्मी बढ़ते ही सुराही, मटका सहित अन्य मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ गई है। ग्रामीण हाट बाजार में मिट्टी के बर्तनों की दुकानें सज गई हैं। सार्वजनिक प्याऊ लगाने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी मिट्टी के बर्तन खरीदना शुरू कर दिया है।

जिन घरों में फ्रिज हैं, वहां भी मटका और सुराही की खरीद हो रही है। सुराही 75 से 280 रुपए में मिल रही है। मटका 60 से 180 रुपए में उपलब्ध है। तापमान बढ़ते ही फ्रिज के साथ ठंडे पानी के लिए मिट्टी के मटकों की जरूरत बढ़ गई है।

लगातार बढ़ते तापमान के कारण पिछले 15 दिनों में मटकों की बिक्री तीन गुना तक बढ़ गई। नगर के प्रमुख स्थल परशुराम चौराहा पर मटके बिक रहे हैं।

रीवा रेंज में व्हाट्सऐप लीक का खेल! गोपनीयता तार-तार, मुखबिरों की जान पर मंडरा रहा खतरा

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा रेंज में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर एक बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि जिन सूचनाओं को सख्त गोपनीयता में रखा जाना चाहिए वही अब व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर परोसी जा रही हैं। इस कथित लापरवाही ने न सिर्फ पुलिस सिस्टम की साख को झटका दिया है बल्कि मुखबिरों की सुरक्षा को भी सीधे खतरे में डाल दिया है। सूत्र बताते हैं कि कई मामलों में कार्रवाई से पहले ही पूरी प्लानिंग और जानकारी व्हाट्सऐप ग्रुप्स में वायरल हो जाती है। इतना ही नहीं कुछ मामलों में यह जानकारी यूट्यूब चैनलों तक भी पहुंच रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किस स्तर पर यह लीक हो रहा है और क्यों? क्या कुछ अधिकारी फेमस होने की चाह में विभागीय नियमों को दरकिनार कर रहे हैं?

मामला यहीं खत्म नहीं होता। जानकारों के मुताबिक इस तरह की लीक से अपराधियों को पहले ही भनक लग जाती है जिससे वे या तो फरार हो जाते हैं या सबूत मिटाने में सफल हो जाते हैं। इसका सीधा असर पुलिस की कार्रवाई पर पड़ता है जो पहले से ही धीमी गति के आरोपों से घिरी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा खतरा उन मुखबिरों को है जो अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस को महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं। यदि उनकी पहचान उजागर होती है तो यह उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। पहले भी सोहागी थाना क्षेत्र की सोनौरी चौकी से जुड़ा मामला सामने आया था जिसमें आरोप लगे थे कि पुलिस खुद मुखबिर तक पहुंचकर दबाव बनाने का प्रयास कर रही थी। अब सेमरिया थाना क्षेत्र की हालिया घटनाएं भी इसी ओर इशारा कर रही हैं कि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई अब उस पैसेंजर ट्रेन जैसी हो गई है जो हर स्टेशन पर रुकती है। यानी ना तो कार्रवाई में तेजी है और ना ही गोपनीयता का पालन। मेमोरेन्डम के आरोपियों को समय पर न्यायालय में पेश करने के बजाय उन्हें थानों में मेहमान की तरह रखने के आरोप भी सामने आ रहे हैं जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का मानना है कि यह केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि एक गंभीर सुरक्षा खामी है। यदि समय रहते इस पर कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो पूरा मुखबिर नेटवर्क ध्वस्त हो सकता है जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे।

बीना में दो बाइकों की भिड़ंत, तीन गंभीर घायल; प्राथमिक इलाज के बाद तीनों को सागर रेफर किया

मीडिया ऑडीटर, बीना (निप्र)। बीना के कुरवाई रोड स्थित बायपास पर बुधवार सुबह दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक इलाज के बाद तीनों घायलों को गंभीर हालत में सागर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, एक बाइक पर कृष्णकांत सिंह राजपूत (20) पिता चिमन सिंह राजपूत निवासी ग्राम बागोदा, कुरवाई सवार थे। दूसरी बाइक पर हर्ष साहू (18) पिता शिवनारायण साहू और शुभम सेन (18) पिता अजय सेन, दोनों निवासी कुरवाई सवार थे।

घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया: शहर के कुरवाई रोड पर दोनों बाइकों की जोरदार टक्कर हुई। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया।

सिविल अस्पताल में डॉ. संजीव अग्रवाल ने घायलों का प्राथमिक इलाज किया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए तीनों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, सागर रेफर कर दिया गया।

घायल कृष्णकांत सिंह राजपूत ने बताया कि वह कुरवाई रोड पर जा रहे थे, तभी अचानक सामने से आ रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिस से वे घायल हो गए।

सामूहिक आयोजनों में परंपरागत भट्टियों का उपयोग

मीडिया ऑडीटर, बामंदी (निप्र)। युद्ध व विषम परिस्थितियों से पैदा हुई रसोई गैस की किल्लत का असर अब त्योहारों पर दिखने लगा है। क्षेत्र में गणगौर पर्व पर इस बार गैस चूल्हों की जगह ईंट व मिट्टी की पारंपरिक भट्टियां का आयोजन सामूहिक भोज में हुआ। सिलेंडर नहीं मिलने से ग्रामीणों को पुराने तरीके अपनाने पड़े। गांव में गणगौर पर्व श्रद्धा व उत्साह से मनाया गया। हर साल की तरह इस बार भी मनोरथी परिवारों ने सामूहिक भोज रखा। इसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों ने शामिल होकर प्रसादी ली। सुभाष पटेल ने बताया युद्ध व विषम हालात से गैस सप्लाय प्रभावित हो रही है। गैस टंकियों की उपलब्धता में कमी आई। किल्लत को देखते हुए भट्टियों की व्यवस्था की गई। आयोजन स्थल पर बड़े स्तर पर ईंट व मिट्टी से भट्टियां बनाई गई। गोबर के कंडों की व्यवस्था भी की। कड़वा पटेल ने बताया लकड़ी की भट्टियों से पुरानी संस्कृति व स्वाद भी लौटा। पारंपरिक चूल्हे का खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है।

गैस किल्लत का असर अब शादी आयोजनों पर भी पड़ता दिख रहा है। गणगौर के बाद क्षेत्र में विवाह आयोजनों का सिलसिला शुरू होगा। पंगत व दूसरे कामों में रसोई गैस की जरूरत पड़ेगी। किल्लत के कारण आयोजन वाले परिवार पहले से गैस टंकियों की जुगत में लगे हैं। परिचितों और रिश्तेदारों से टंकियां जुटाई जा रही हैं।

मंदसौर के रिहायशी इलाके में घुसा 6 फीट लंबा मगरमच्छ डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद चंबल नदी में छोड़ा; वन विभाग ने पकड़ा

मीडिया ऑडीटर, मंदसौर (निप्र)। मंदसौर जिले के संजीत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दोबड़ा में मंगलवार देर रात एक 6 फीट लंबा मगरमच्छ रहवासी इलाके में घुस आया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रात 1 बजे मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू किया। टीम ने रेस्क्यू किए गए मगरमच्छ को रात करीब 2:30 बजे संजीत से होकर गुजरने वाली चंबल नदी के बैकवॉटर क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया है। गनीमत रही कि इस दौरान मगरमच्छ ने किसी ग्रामीण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वन विभाग की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया।

रात 11:30 बजे मिली सूचना, 1 बजे हुआ रेस्क्यू: ग्राम दोबड़ा में मंगलवार देर रात मगरमच्छ को रहवासी इलाके में देखकर ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया था और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी।

रात करीब 11:30 बजे सूचना मिलने के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद करीब 1 बजे 6 फीट लंबे मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू किया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग डेढ़ घंटे का समय लगा।

रेस्क्यू टीम में ये अधिकारी और कर्मचारी रहे शामिल: वन विभाग के अधिकारी पुष्कर मालवीय के निर्देशन में इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। रेस्क्यू टीम के सदस्य जितेन्द्र सिंह पंवार (वन रक्षक), कादर गोंदिया और दीपक नागर ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू की कार्रवाई शुरू की और सुरक्षित तरीके से मगरमच्छ को पकड़ा। रात 2:30 बजे चंबल नदी के बैकवॉटर में छोड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से चंबल नदी के बैकवॉटर क्षेत्र में छोड़ दिया। यह बैकवॉटर क्षेत्र संजीत से होकर गुजरता है। टीम ने रात करीब 2:30 बजे मगरमच्छ को वहां छोड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

महिला बोली- पति का पड़ोसन से अफेयर, मुझे जहर पिलायाछत्तरपुर में कहा- अवैध संबंध का विरोध करने पर पीटा, सास पर भी आरोप

मीडिया ऑडीटर, छतरपुर (निप्र)। छतरपुर के बगौता गांव में एक महिला को उसके पति और सास ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ पिला दिया। महिला की हालत गंभीर है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। पीड़िता पूनम सेन ने आरोप लगाया है कि उनके पति सोनू सेन के पड़ोस में रहने वाली एक महिला से अवैध संबंध हैं। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पूनम ने बताया कि उन्होंने इस संबंध का कई बार लिखित शिकायत के माध्यम से भी विरोध किया था। पूनम के अनुसार, इसी विवाद को लेकर वर्ष 2024 में एक समझौता भी हुआ था, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी महिला उन्हें ताने मारती थी और 'प्यार करने वाले कभी डरते नहीं' जैसे गाने गाकर चिढ़ाती थी। हाल ही में जब पूनम ने फिर से इस संबंध का विरोध किया, तो विवाद बढ़ गया। पूनम का आरोप है कि इसी दौरान पति और सास ने उनके साथ मारपीट की। जब वह घर छोड़कर पुलिस में शिकायत करने जा रही थीं, तो उन्हें रोककर घर में बंद कर दिया गया। पीड़िता ने बताया कि उनके साथ सड़क प र भी सरेआम मारपीट की गई और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की गई। उनके गले पर अभी भी चोट के निशान मौजूद हैं। इसके बाद उन्हें जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया गया। पूनम सेन का यह भी कहना है कि उनके पति और दूसरी महिला के बीच इंस्टाग्राम पर चैटिंग और वीडियो कॉलिंग होती थी। उन्होंने दोनों को आपत्तिजनक हालत में भी देखने का दावा किया है। पूनम सेन की शादी को लगभग 10 साल हो चुके हैं और उनके दो बच्चे हैं।

उन्होंने पुलिस से पति और सास के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता और उनके मायके पक्ष के परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही है। हालांकि, पुलिस को अभी तक इस मामले की औपचारिक जानकारी नहीं मिली है। सिविल लाईन टीआई सतीश सिंह का कहना है कि इस तरह का मामला और जानकारी सामने आई है पीड़िता के परिजनों को थाने बुलवाया है उनकी शिकायत पर जांच कर विधि संवत कार्रवाई की जाएगी।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी बिकी

विश्व के सबसे अमीर क्रिकेटर की अगुआई वाले ग्रुप ने खरीदा

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)को आदित्य बिड़ला ग्रुप (ABG), द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप (ToI), बोल्ट वेंचर्स (बोल्ट) और ब्लैकस्टोन्स परपेचुअल प्राइवेट इक्विटी स्ट्रैटेजी (BXPE, ब्लैकस्टोन) ने मिलकर 1.78 बिलियन डॉलर (लगभग 16,706 करोड़ रुपये) में खरीद लिया है। इस डील के बाद आरसीबी के चेयरमैन आदित्य बिड़ला ग्रुप के डायरेक्टर आर्यमन विक्रम बिड़ला होंगे।

आर्यमन खुद पेशेवर क्रिकेटर हैं। वह दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के सत्यन गजवानी फ्रेंचाइजी के उप-चेयरमैन होंगे। इस कंसोर्टियम में शामिल अन्य लोग बोल्ट वेंचर्स के फाउंडर डेविड ब्लिट्जर और बीएक्सपीई के सीईओ विरल पटेल हैं। क्रिकबज के अनुसार इन चार ग्रुप्स के एक ग्रुप ने आरसीबी की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए डियागो की सब्सिडियरी कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (USL) के साथ एक समझौते पर साइन किया है। इसमें आरसीबी की आईपीएल और डब्ल्यूपीएल दोनों

टीमें शामिल हैं।

आईपीएल 2026 में आरसीबी को कौन चलाएगा- आरसीबी की बिक्री को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अलावा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और अन्य नियामक संस्थाओं से मंजूरी की आवश्यकता होगी। ऐसे में आईपीएल 2026 में डियागो ही आरसीबी को चलाएगा। आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने एक बयान में कहा, 'पिछले दो दशकों में आईपीएल वैश्विक स्तर पर खेल का पावरहाउस बना है, जिसने भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल दिया है और भारत की गरिमा को बढ़ाया है। आधुनिक समय मे आरसीबी सबसे जबरदस्त फ्रेंचाइजी में से एक है, जो आदित्य बिड़ला ग्रुप को अपनी विरासत को वैश्विक खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म देती है। हम इस संपत्ति के संरक्षक बनकर खुश हैं और इस असाधारण विरासत को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

आर्यमन बिड़ला ने क्या कहा?

नए चेयरमैन आर्यमन बिड़ला ने फ्रेंचाइजी अध्यक्षता करना अपने लिए सम्मान की बात मानी। उन्होंने कहा, ' अगले चरण में आरसीबी के विकास को आकार देने के लिए इस साझेदारी में साथ आना सम्मान की बात है। यह साझेदारी खेल, मीडिया और उपभोक्ता व्यवसाय की गहरी समझ लाती है।'

चेन्नई में एलिस की जगह लेगा 2024 में 10 करोड़ में बिका खिलाड़ी, दिल्ली को बड़ा झटका

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के चोटिल गेंदबाज नाथन एलिस की जगह उनके हमवतन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन को जोड़ा है। जॉनसन को आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस ने 10 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा। जॉनसन ने आईपीएल में 9 मैच खेले हैं। वह कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का भी हिस्सा रहे हैं। इस बीच दिल्ली कैपिटल्स (DC) को बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज बेन डकेट ने आईपीएल 2026 में खेलने से मना कर दिया है। वह इंग्लैंड के लिए अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं।

पिछले साल कोलकाता के लिए खेले थे जॉनसन

31 साल के एलिस 11 मार्च को घरेलू वनडे टूर्नामेंट के फाइनल के दौरान हैमस्ट्रिंग की चोट दोबारा उभरने के बाद पूरे सीजन से बाहर हो गए थे। पांच बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने जॉनसन को टीम में शामिल करने के लिए तेजी दिखाई है, जो पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए चार मैच खेले थे।

ईरान-इजरायल युद्ध का असर

ईंधन संकट से जूझता पाक, दर्शकों और उद्घाटन समारोह के बगैर होगा PSL 2026

नई दिल्ली, एजेंसी। ईरान-इजरायल युद्ध की आग अब खेल की दुनिया तक पहुंचती दिख रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पैदा हुए ईंधन संकट का सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ा है। पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के मैच अब खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। हालात ऐसे हैं कि सरकार ने लोगों से आवाजाही कम करने की अपील की है। इससे टूर्नामेंट की रौनक पर असर पड़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी परिस्थितियों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। शुरुआती मुकाबलों में दर्शकों के प्रवेश पर रोक रहेगी और मैच सिर्फ कराची और लाहौर में खेले जाएंगे। यही नहीं, टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह भी रद्द कर दिया गया है।

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का सीजन 26 मार्च से शुरू होगा। प्रशंसकों को स्टैंड्स में आने की मंजूरी नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) का 'खर्च में कटौती' वाला यह कदम, इजरायल और अमेरिका का ईरान के साथ जारी युद्ध का परोक्ष नतीजा है।

नहीं पता कब तक चलेगा संकट : मोहसिन नकवी

इन उपायों के बारे में बताते हुए क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने पूरे पाकिस्तान से अपील की थी कि ईंधन संकट के चलते लोग अपनी आवाजाही सीमित रखें। हमने स्कूल बंद कर दिए, 'वर्क फ्रॉम होम' लागू किया और ईद की छुट्टियों की संख्या बढ़ा दी। हमें नहीं पता कि यह संकट कब तक चलेगा।' मोहसिन नकवी ने कहा, 'इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा एजेंसियों से चर्चा करने के बाद, हमने फैसला किया कि क्रिकेट अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही होगा, लेकिन हम लोगों से यह नहीं कह सकते कि वे अपनी आवाजाही सीमित रखें और फिर हर दिन क्रिकेट मुकाबलों के लिए स्टेडियम में 30 हजार लोगों की भीड़ जमा होने दें।' मोहसिन नकवी ने कहा, 'हमने फैसला किया है कि जब तक यह संकट जारी रहेगा, हम मैचों में दर्शकों को आने की अनुमति नहीं देंगे। यह एक मुश्किल फैसला था, लेकिन इसे लेना जरूरी था। उद्घाटन समारोह भी रद्द कर दिया जाएगा।' मोहसिन नकवी पाकिस्तान सरकार में गृह मंत्री भी हैं।

फ्रेंचाइजियों के नुकसान की भरपाई करने की करेंगे कोशिश

पीसीबी (क्रिकेट बोर्ड) ने ऐलान किया कि बोर्ड आठ फ्रेंचाइजियों को पहले से घोषित स्थानों फैसलाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और मुल्तान पर अनुमानित गेट मनी का भुगतान करके उनकी भरपाई करने की कोशिश करेगा। मोहसिन नकवी ने कहा, 'मैं पेशावर के लोगों से माफी मांगना चाहूंगा।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग का नया शेड्यूल जारी किया है

मोहसिन नकवी ने कहा, 'हम यह पक्का करेंगे कि भविष्य में किसी न किसी रूप में उनकी भरपाई की जाए। क्रिकेट एक इंटरनेशनल ब्रांड है और हमारा गौरव है।' मोहसिन नकवी ने इस बात की पुष्टि की कि क्रिकेट के लिए विदेशी खिलाड़ी रविवार रात से पाकिस्तान पहुंचना शुरू कर देंगे।

क्रिकेटर रिंकू सिंह को योगी सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी, इस पद पर मिली नियुक्ति

लखनऊ, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को खेल कोटे के तहत रिंकू का नियुक्ति पत्र जारी किया हालांकि, वह अपरिहार्य कारणों से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। खेल विभाग के निदेशक डॉ. आर. पी. सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि रिंकू सिंह इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी फ्रेंचाइजी से जुड़े कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि रिंकू ने जल्द ही लखनऊ आकर खेल निदेशालय में कार्यभार ग्रहण करने की बात कही है। खेल निदेशक के अनुसार, रिंकू को उनकी योग्यता के अनुरूप कार्यक्षेत्र दिया जाएगा ताकि वह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपनी सेवाएं जारी रखते हुए अपने प्रशासनिक दायित्व भी निभा सकें। राज्य सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, पांच खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और चार खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया। अधिकारियों के मुताबिक, हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, पैरा एथलीट अजीत सिंह और सिमरन को जिला पंचायत राज अधिकारी तथा पैरा एथलीट प्रीति पाल को खंड विकास अधिकारी पद के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। इसके अलावा, हॉकी खिलाड़ी उत्तम सिंह, जिम्नास्ट अभिजीत कुमार, पहलवान जोंटी कुमार, पैरा कैनोइंग खिलाड़ी यश कुमार और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के तहत प्रत्येक खिलाड़ी को तीन लाख 11 हजार रुपये, कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि एथलीट प्राची व तान्या चौधरी, पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी प्रगति केसरवानी और शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार के तहत भी प्रत्येक खिलाड़ी को तीन लाख 11 हजार रुपये, कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। बयान के अनुसार, विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले 14 खिलाड़ियों को भी पुरस्कार राशि प्रदान की गई। पैरा पावरलिफ्टिंग खिलाड़ी विनय को 40 लाख रुपये, वुशु खिलाड़ी विक्रांत बालियान, निशानेबाज सागर दांगी, पर्वतारोही दीपक कुमार और लेफ्टिनेंट जनरल भानु पाठक को 15-15 लाख रुपये दिए गए। इसके अलावा, सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी तनुश्री पांडे व ओम यादव को क्रमशः 14 लाख और 12 लाख रुपये, हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल और पैरा कैनोइंग खिलाड़ी यश कुमार को 10-10 लाख रुपये प्रदान किए गए। सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी मुस्कान यादव को छह लाख, कयाकिंग एवं कैनोइंग खिलाड़ी अभय सिंह को पांच लाख, निशानेबाज श्रवण कुमार को तीन लाख, निशानेबाज यश तोमर और ईशान खान को दो-दो लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी गई। कार्यक्रम में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सिमरन शर्मा और हॉकी खिलाड़ी उत्तम सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को दिए जा रहे प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार की सराहना की।

एमएमए के बारे में 2024 तक नहीं जानते थे संग्राम सिंह भतीजे की वजह से आजमाया हाथ

नई दिल्ली, एजेंसी। पहलवान से मिक्सड मार्शल आर्ट्स (रूस) फाइटर बने संग्राम सिंह ने फ्रांस के फ्लोरियन काउड्रे के साथ अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में होने वाली फाइट से पहले एमएमए में जाने के बारे में बताया। संग्राम ने कहा कि वह 2024 से पहले तक एमएमए के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने अपने भतीजे की वजह से एमएमए में करियर बनाने के बारे में सोचा। 40 साल के संग्राम ने बताया कि वह 7 कोचों के साथ मेहनत करते हैं।

संग्राम ने एमएमए में करियर बनाने के बारे में बताया, 'मुझे 2024 से पहले एमएमए के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन अभी भारत के युवाओं के बीच दो खेल बहुत प्रसिद्ध है। एक है फुटबॉल और दूसरा एमएमए है। 2024 में मेरा रेसलिंग करियर लंबा रहा है, लेकिन जब मैंने अपने भतीजे से बात की तो उसने कभी मेरी कोई रेसलिंग बाउट नहीं देखी थी, लेकिन वह सभी यूएफसी फाइटर्स को पहचानता है। आज भारत में एमएमए के लगभग 1 लाख खिलाड़ी हैं।'

एमएमए की वजह से बनी पहचान : संग्राम ने एमएमए की लोकप्रियता पर कहा, 'अब तक मैंने जितने भी एमएमए मुकाबले लड़े हैं उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है। मुझे नहीं पता कि लोगों दिलचस्पी यूएफसी और एमएमए की प्रसिद्धि की वजह से हो या 40 साल की उम्र में मेरे मुकाबले में हिस्सा लेने से बढ़ रही हो। आज युवा मुझे मेरे टीवी करियर की वजह से नहीं, बल्कि मेरे एमएमए की वजह से पहचानते हैं।'

दारा सिंह बनोगे : संग्राम ने 40 साल की उम्र में लड़ने पर कहा, 'बहुत से लोग मेरा मनोबल बढाते हैं। मेरे कोच कहते हैं कि शरीर की उम्र 22 साल है। मेरी पत्नी पायल रोहतगी ने मुझसे कहा कि अगर तुम अभी मुकाबला नहीं करोगे तो कब करोगे, जब मैंने मिट्टी में कुश्ती शुरू की तो मुझे चोटें लगती थीं मेरी मां गर्म रूई से मेरी चोटों की मालिश करती थीं और वह मुझे यह कहती थीं कि तुम दारा सिंह बनोगे।'

मिट्टी वाली कुश्ती दिल के करीब : संग्राम ने कहा, 'मैंने कुल सात कोच के साथ काम किया। भूपेश सर के साथ कुश्ती की। बीजेजे के लिए अहमदाबाद गया। मैंने वेट ट्रेनिंग, जिमनास्टिक वगैरह किया। इस बार पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण विमान 28 घंटे लंबी होगी। मैंने मिट्टी की रेसलिंग से शुरुआत की जो फिर मैट की ओर बढ़ी। आखिरकार अब एमएमए कर रहा हूं, लेकिन मिट्टी वाली कुश्ती हमेशा मेरे दिल के सबसे करीब रही है।

युवाओं को सलाह : संग्राम ने कहा कि युवाओं को कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर जैसे फास्ट फूड से बचना चाहिए और प्राकृतिक खाना खाना चाहिए।

ट्रिपल एच ने किया एक और भयंकर मैच का ऐलान

10 साल बाद उतरेंगी एजे ली

नई दिल्ली, एजेंसी। WWE के मेगा इवेंट रेसलमेनिया 42 के आयोजन में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है। इसी बीच कंपनी के चीफ कंटेंट ऑफिसर ट्रिपल एच ने एक और बड़े मुकाबले का ऐलान किया है। एच ने मंगलवार सुबह एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए एक भयंकर मुकाबले की घोषणा की। उन्होंने मंडे नाइट रॉ के बाद एजे ली और बैकी लिंच के रेसलमेनिया मैच को ऑफिशियल किया। दोनों का सामना मेगा इवेंट में वुमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के तहत होगा।

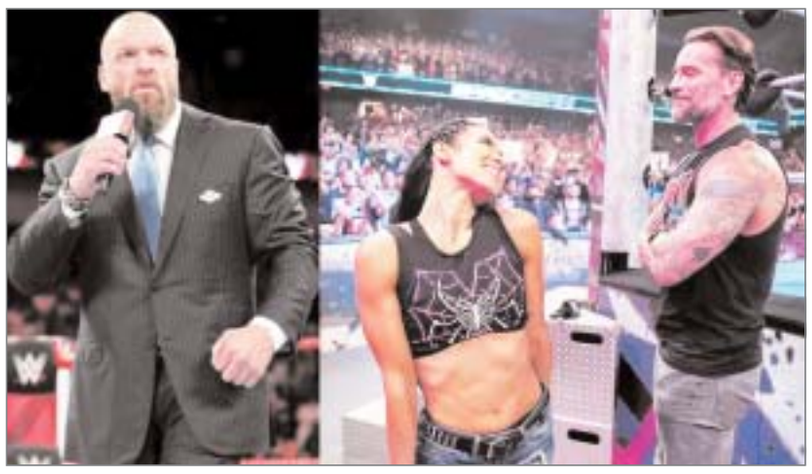

10 साल बाद रेसलमेनिया में उतरेंगी एजे ली- आपको बता दें कि हाल ही में एजे ली ने एलिमिनेशन चैंबर में बैकी लिंच को हराया था। इसी के बाद यह बवाल और बढ़ गया। फिर पिछले हफ्ते रॉ के एपिसोड में एजे पर बैकी लिंच ने हमला किया था। उसके बाद सोमवार को इस हफ्ते के रॉ के एपिसोड में फिर दोनों के बीच जुबानी जंग देखन को मली।

आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले भारतीय 16 साल से मुरली नंबर 1

संजू, गिल और श्रेयस एक ही स्थान पर

नई दिल्ली, एजेंसी। आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी और इस सीजन में भी हमें कई बड़ी पारियां देखने को मिल सकती हैं। ये आईपीएल का 19वां सीजन होगा, लेकिन इससे पहले यानी पिछले 18 सीजन में ऐसे कई बल्लेबाज हुए हैं जिन्होंने गजब की बैटिंग की है और छक्के लगाने में भी कमाल किया है। आईपीएल में ओवरऑल एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर तो क्रिस गेल थे जिन्होंने साल 2013 में अपनी इनिंग के दौरान कुल 17 छक्के लगाए थे जो अब तक नहीं टूटा है तो वहीं इस लीग की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर्स की करें तो इसमें भी कई दिग्गज शामिल हैं। हालांकि गेल से आगे तो कोई नहीं निकल पाया, लेकिन छक्के लगाने में भारतीय बैटर्स ने भी कमाल किया है।

मुरली विजय टॉप पर

आईपीएल में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर मुरली विजय हैं जिन्होंने साल 2010 में राजस्थान के खिलाफ अपनी पारी के दौरान 11 छक्के लगाए थे और ये रिकॉर्ड अब तक कायम है। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल एक साथ यानी संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। इन तीनों बल्लेबाजों ने आईपीएल में अपनी पारी के दौरान 10-10 छक्के लगाने का कमाल किया है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर कुल 9 बल्लेबाज शामिल हैं जिन्होंने आईपीएल की एक पारी में 9-9 छक्के लगाए थे। तीसरे नंबर पर जो बल्लेबाज संयुक्त रूप से मौजूद हैं उनमें युवराज सिंह, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पंड्या, संजू सैमसन, इशान किशन, रॉबिन उथप्पा, ऋतुराज गायकवाड़, वेंकटेश अय्यर शामिल हैं।

एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-4 भारतीय

मुरली विजय- 11 छक्के बनाम राजस्थान, 2010
संजू सैमसन- 10 छक्के बनाम आरसीबी, 2018
श्रेयस अय्यर- 10 छक्के बनाम केकेआर, 2018
शुभमन गिल- 10 छक्के बनाम मुंबई, 2023
युवराज सिंह- 9 छक्के बनाम डेयरडेविल्स, 2014
ऋषभ पंत- 9 छक्के बनाम गुजरात, 2017
दिनेश कार्तिक- 9 छक्के बनाम राजस्थान, 2019
हार्दिक पंड्या- 9 छक्के बनाम कोलकाता, 2019
संजू सैमसन- 9 छक्के बनाम सीएसके, 2020
इशान किशन- 9 छक्के बनाम आरसीबी, 2020
रॉबिन उथप्पा- 9 छक्के बनाम आरसीबी, 2022
ऋतुराज गायकवाड़- 9 छक्के बनाम गुजरात, 2023
वेंकटेश अय्यर- 9 छक्के बनाम मुंबई, 2023
यूसुफ पठान- 8 छक्के बनाम मुंबई, 2010
वीरेंद्र सहवाग- 8 छक्के बनाम सीएसके, 2014
रिद्धिमान साहा- 8 छक्के बनाम केकेआर, 2014

खेलो इंडिया ट्राइबल गेस छीसगढ़ के लिए मील का पत्थर

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी के लिए छत्तीसगढ़ पूरी तरह तैयार है और राज्य के उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव का मानना है कि यह 'राज्य के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को बड़ा बढ़ावा देगा।' खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री साव ने मंगलवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स भारतीय खेल इतिहास में एक 'मील का पत्थर' साबित होगा। श्री साव ने बताया कि, 'हमने पहले सरगुजा ओलंपिक और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन छोटे स्तर पर किए हैं। अब खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी कर हम एक बड़े मंच पर कदम रख रहे हैं, जो हमारी क्षमताओं की परीक्षा भी लेगा और उन्हें नई ऊंचाई देगा। 'उन्होंने कहा, 'यह छत्तीसगढ़ के लिए निस्संदेह एक ऐतिहासिक और यादगार आयोजन है। यह हमारे खेल प्रतिभा और बुनियादी ढांचे को बड़ी मजबूती देगा। साथ ही, यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के आयोजन का प्रत्यक्ष अनुभव भी प्रदान करेगा। '

श्री साव ने बताया कि, 'राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाले खिलाड़ियों के साथ खेलने और उन्हें देखने का अनुभव छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए बेहद समृद्ध करने वाला होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह आयोजन राज्य के खेल तंत्र और खिलाड़ियों दोनों के लिए बड़ी ताकत साबित होगा। '

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा लेंगे और कुल नौ खेलों का आयोजन होगा। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती में पदक दिए जाएंगे, जबकि मल्लखंब और कबड्डी प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल होंगे। करीब 3,800 प्रतिभागी इन खेलों में हिस्सा लेंगे, जो 3 अप्रैल तक चलेंगे। प्रतियोगिताएं रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित की जाएंगी। कुल 106 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे। एथलेटिक्स में सर्वाधिक 34 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। तैराकी (24), कुश्ती (18), वेटलिफ्टिंग (16) और तीरंदाजी (10) में भी दो अंकों में स्वर्ण पदक होंगे। हॉकी और फुटबॉल टीम खेल हैं, जिनका आयोजन रायपुर में होगा। एथलेटिक्स जगदलपुर में और कुश्ती सरगुजा में आयोजित की जाएगी। भारत के शीर्ष खिलाड़ी, हॉकी ओलंपियन दिलीप तिर्की, सलीमा टेटे और शीर्ष धावक अनिमेष कुजूर ने कहा, 'खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स खेलों में करियर बनाने और आदिवासी समुदाय से निकले दिग्गज खिलाड़ियों से प्रेरणा लेने का एक शानदार मंच है। '

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और पूर्व ओलंपियन दिलीप तिर्की ने साई मीडिया से कहा, 'मेरे लिए और हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि देश में पहली बार इस तरह की चौंपियनशिप शुरू हो रही है। यह युवाओं और आदिवासी खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और खेलों में आगे बढ़ने, तथा देश के लिए खेलने का एक बेहतरीन अवसर है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विज़न है कि भारत एक खेल राष्ट्र बने। वे चाहते हैं कि हर युवा किसी न किसी खेल से जुड़ा रहे। ' मेजबान राज्य छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और असम से 100 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पुरुष और महिला खिलाड़ियों का अनुपात लगभग 50-50 रहेगा, जो ओलंपिक चार्टर में लैंगिक समानता के सिद्धांत के अनुरूप है।

दिलीप तिर्की ने बताया कि, 'केन्द्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया भी चाहते हैं कि खेलों के माध्यम से हमारे खिलाड़ी, खासकर आदिवासी खिलाड़ी, बेहतर करियर बना सकें, अपने जीवन को सुधार सकें और देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। मैं स्वयं एक आदिवासी परिवार से आता हूं और खेलों, विशेषकर हॉकी के माध्यम से आज यहां तक पहुंचा हूं। मुझे विश्वास है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी आदिवासी बच्चों का भविष्य उज्ज्वल है। पहले भी कई आदिवासी खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया है और वे हमारे समाज के प्रेरणास्रोत बने हैं। '

राष्ट्रीय 100 मीटर और 200 मीटर रिकॉर्ड धावक और भारत के उभरते एथलेटिक्स स्टार अनिमेष कुजूर ने साई मीडिया से कहा, 'भारत में अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां खेल पूरी तरह नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन और भी खास बन जाता है। मैं सरकार के इस प्रयास की सराहना करता हूं, जिसने देशभर के आदिवासी युवाओं को एक मंच पर लाने का काम किया है।'

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के इस उद्घाटन संस्करण में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित ट्रायल्स के माध्यम से किया गया है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भारतीय खेल प्राधिकरण (सांई) द्वारा नियुक्त कोच नजर रखेंगे। श्री तिर्की ने कहा, 'हमारे सभी आदिवासी खिलाड़ी और बच्चे खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाएं, देश के लिए खेलें और अपना करियर बनाएं। प्रधानमंत्री का 2036 ओलंपिक और विकसित भारत का विज़न है कि हमारा देश एक युवा और खेल राष्ट्र बने। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन हमारा देश एक सशक्त खेल राष्ट्र के रूप में उभरेगा। '

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अपेक्स कमेटी की बैठक सम्पन्न

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की अपेक्स कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गतिविधियों, वित्तीय वर्ष 2025-26 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, वित्तीय वर्ष 2026-27 के एक्शन प्लान, स्वच्छता के लिए नवाचार तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु अंतर्विभागीय अभिसरण पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में अधिकारियों को अपशिष्ट प्रबंधन अधोसंरचना के तहत गांवों में कम्पोस्ट पिट, सोखता गड्ढा और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा गया है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्रामों की स्वच्छता के कार्यों की सर्टिफिकेशन ग्राम सभा द्वारा कराया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने भारत स्वच्छ मिशन के अंतर्गत राज्य के सभी ग्रामों में स्वच्छता के कार्यों को नियमित रूप से मॉनिटरिंग कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए है। गांवों के हाट-बाजारों में सामूहिक शौचालय का उपयोग एवं स्वच्छता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी तरह से आवश्यकतानुसार सामूहिक शौचालय की उपयोगिता एवं रखरखाव सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्थलों पर करीब 14 हजार 279 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। इसी तरह से वर्ष 2026-27 में 2014 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक कार्ययोजना के निर्माण के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने इस हेतु देश के अन्य राज्यों के सफल प्लास्टिक वेस्ट मैंनेजमेंट के मॉडल को अपनाने की बात कही। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक वेस्ट से सशक्त सड़कों के निर्माण करने की अभिनव एवं सतत् पहल की जा रही है। राज्य के बस्तर, महासमुंद, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में प्लास्टिक मिक्स डामर रोड निर्माण किए जा रहे हैं। रोड निर्माण में करीब 3000 किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक का उपयोग किया गया है। राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता, जल प्रबंधन एवं प्रशासनिक व्यवस्था की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन करने हेतु स्वच्छ पंचायत पोर्टल की शुरूआत की गई है। ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा ग्राम की स्वच्छता, जल आपूर्ति एवं प्रशासन की ऑनलाइन प्रविष्टि की जा रही है।

बस्तर का समग्र विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता- मंत्री केदार कश्यप

वन मंत्री कश्यप ने मुरकुची और पखना कोंगेरा में दी विकास कार्यों की सौगात

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने विकास की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि बस्तर का समग्र विकास केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे धरातल पर उतारना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों की राह में आने वाली हर बाधा को दूर करना उनका लक्ष्य है।

मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बस्तर विकासखंड में विकास की नई इबारत लिखी। उन्होंने क्षेत्र के सघन दौरे के दौरान मुरकुची और पखना कोंगेरा में आयोजित भव्य कार्यक्रमों मंस शिरकत की, जहाँ उन्होंने विधायक निधि से स्वीकृत कुल 56 लाख रूपए की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत भूमिपूजन कर ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 10 महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई, जिससे स्थानीय स्तर पर आवागमन और सामुदायिक सुविधाओं में व्यापक सुधार सुनिश्चित होगा।

जनसमूह को संबोधित करते हुए मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुलियाओं का निर्माण केवल ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं है, बल्कि यह गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने वाली जीवनरेखा है। उन्होंने पूर्ववर्ती कठिनाईयों का स्मरण कराते हुए कहा कि बरसात के दिनों में छोटे-छोटे नालों के उफान पर होने के कारण ग्रामीणों, विशेषकर स्कूली बच्चों और मरीजों को जो परेशानियां झेलनी पड़ती थीं, अब ये नई पुलियाएं उन समस्याओं का स्थायी समाधान बनेंगी।

डिजिटल सेवा केंद्र से बदली रानी कुर्रे की जिंदगी, बनीं आत्मनिर्भर

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणा बनकर उभरीं रानी कुर्रे ने अपने प्रयासों और डिजिटल तकनीक के उपयोग से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की है। कोरिया जिले के शिखा महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य रानी, ग्राम रनई की निवासी हैं और ज्योति क्लस्टर, पटना से जुड़ी हुई हैं। आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जीवनयापन कर रही रानी ने बिहान योजना के तहत अपने समूह से 50 हजार रुपये का ऋण प्राप्त कर वर्ष 2024-25 में कस्टमर सर्विस सेंटर।की शुरुआत की। इस केंद्र के माध्यम से वे आधार, पैन कार्ड, बिल भुगतान और विभिन्न सरकारी सेवाएं ग्रामीणों तक पहुंचा रही हैं। शुरुआत में डिजिटल सेवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनका विश्वास जीतना आसान नहीं था, लेकिन रानी ने धैर्य और निरंतर प्रयासों से धीरे-धीरे अपनी पहचान बना ली। आज उनका केंद्र गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र बन चुका है। रानी की मेहनत का परिणाम है कि आज वे सालाना लगभग 1 लाख 50 हजार रुपए की आय अर्जित कर रही हैं, जबकि उनकी मासिक आय 14 हजार से 14 हजार 500 रुपए तक पहुंच गई है। इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। रानी कुर्रे न केवल खुद आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि उन्होंने अपने गांव में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाकर अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया है।

वनों की सुरक्षा को मिला नया कवच- 227 मुनारों का निर्माण पूर्ण

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। वन विभाग में मुनारा निर्माण केवल जमीन की सीमांकन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वनों की सुरक्षा, प्रबंधन और कानूनी स्थिति को मजबूत करने का एक बहुआयामी उपकरण है। मुनारा निर्माण बहुआयामी पहलू हैं। वनों की सुरक्षा और अवैध अतिक्रमण पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के कवर्धा परियोजना मंडल ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कैम्पा मद के अंतर्गत विभिन्न वन परिक्षेत्रों में कुल 227 नए मुनारों (बाउंड्री पिलर) का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। यह कार्य वन सीमाओं के स्पष्ट निर्धारण, संरक्षण और विवादों के स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मुनारा निर्माण की प्रमुख विशेषताएं परियोजना के तहत कवर्धा मंडल के अधिकांश संवेदनशील और महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों में मुनारों का निर्माण किया गया है। इन मुनारों को मजबूत और गुणवत्तापूर्ण सामग्री से तैयार किया गया है, ताकि वे लंबे समय तक टिकाऊ बने रहें। हाल ही में निरीक्षण के दौरान प्रबंध संचालक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रेम कुमार ने इस कार्य की सराहना की। स्पष्ट सीमांकन होने से अब वन रक्षकों और गश्ती दल को निगरानी कार्य में सुविधा होगी और वन क्षेत्र की सुरक्षा अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।

तालाब के ऊपर मुर्गी पालन कर खेती को और अधिक लाभकारी बनाया

अपनी मेहनत और नवाचार से खेती को नई पहचान दे रहा - युवा किसान अंकित

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। खेत को आय का बहुआयामी और मजबूत माध्यम बनाने के लिए पारंपरिक खेती के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों, संबद्ध व्यवसायों और विविधीकरण को अपनाना अनिवार्य है। मुर्गी पालन और मछली पालन को एक साथ अपनाना, जिसे एकीकृत मछली-सह-मुर्गी पालन कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय में भारी बढ़ोतरी और आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन जरिया है। यह प्रणाली कम लागत में दोहरा मुनाफा प्रदान करती है। छत्तीसगढ के जशपुर जिले के ग्राम रतबा के युवा किसान अंकित लकड़ा अपनी मेहनत और नवाचार से खेती को नई पहचान दे रहे हैं। पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर उन्होंने अपने खेत को बहुआयामी आय का मजबूत माध्यम बना दिया है। आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी। ग्राम रतबा के युवा किसान अंकित ने बताया कि पहले वे बरसात में सिर्फ धान की खेती करते थे। इसे पश्चात् उन्होंने मत्स्य विभाग से जानकारी प्राप्त कर अपने खेत में तालाब बनाए। अब वे गर्मी में भी खेती करने लगे और आम के पेड़ लागाए उसी तालाब के पानी से गर्मी में पेड़ों को पानी देते हैं। तालाब के पानी का उपयोग करके बागवानी भी कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि 2 तालाब के उपर शेड बनाकर मुर्गी पालन और मछली पालन करते हैं। मुर्गियों का अपशिष्ट मछलियों के लिए आहार का कार्य करता है। शेड का कैपेसिटी 1000 से 1200 है। तालाब के मेड में आम का पेड़ लगाए हैं। आम का पेड़ या अन्य पेड़ मिट्टी को एकजुट रखता है मिट्टी को काटने नहीं देता। इसके साथ ही आम का पेड़, लीची का पेड़ अतिरिक्त आय का माध्यम बन जाता है।

युवा किसान ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना अंतर्गत पॉन्ड लाइनर प्राप्त हुआ है। मछली विभाग से 8 लाख रूपए की राशि अनुदान में मिला इसके साथ पॉलीथिन, बोर, मोटर और फीड प्राप्त हुआ है। इस मॉडल को अपनाने वाले किसानों का कहना है कि यह न सिर्फ आमदनी बढ़ाता है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। मछली पालन करने वाले नंदकिशोर पटेल बताते हैं कि पहले वे केवल तालाब में मछली पालन करते थे, लेकिन अब उन्होंने इस मॉडल से मुर्गी पालन भी शुरू किया है। उनका कहना है कि 'शुरुआत में थोड़ा इनवेस्टमेंट जरूर लगता है, लेकिन जब सिस्टम चलने लगता है, तो मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलता है। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए, फिर हर महीने स्थिर इनकम होने लगती है।

कल्याणकारी योजनाओं से संवर रहा तनीषा का भविष्य

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। ग्रामीण अंचलों में शिक्षा की अलख जगाने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को संबल देने की शासन की मंशा अब धरातल पर रंग लाती दिख रही है। बस्तर जिले के विकासखण्ड बास्तानार के ग्राम तुरांगुर निवासी किरण ठाकुर की कहानी इसका जीवंत उदाहरण है, जहाँ सरकारी सहायता ने एक पिता के अपनी बेटी को पढ़ाने के संकल्प को नई उड़ान दी है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत किरण ठाकुर अपनी सुपुत्री तनीषा ठाकुर को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए प्रयासरत थे, जो वर्तमान में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत है। इसी दौरान उन्हें अपने एक मित्र के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। शिक्षा के प्रति जागरूक किरण ने बिना देर किए आवश्यक दस्तावेजों के साथ श्रम संसाधन केंद्र में आवेदन किया, जिसके सुखद परिणाम जल्द ही सामने आए।

डीबीटी के माध्यम से किरण ठाकुर के बैंक खाते में मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये की सहायता राशि सीधे हस्तांतरित की गई। इतना ही नहीं, उन्हें निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक-कॉपी सहायता योजना का भी लाभ मिला, जिसके तहत 2,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई।

चमेली के जीवन में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना ने बिखेरी खुशियों की रोशनी

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं ने समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर दिया है, जिसकी एक जीवंत मिसाल बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की ग्राम पंचायत सकरी की निवासी चमेली सेन हैं। पूर्ण रूप से भूमिहीन होने के कारण आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे चमेली के परिवार के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना एक बड़ा संबल बनकर उभरी है।

योजना के तहत प्रतिवर्ष मिलने वाली 10,000 रुपये की सहायता राशि ने न केवल उनके संघर्षों को कम किया है, बल्कि एक गरीब परिवार को समाज में सम्मान के साथ जीने का नया भरोसा भी दिलाया है। चमेली सेन का कहना है कि यह राशि महज एक आर्थिक मदद नहीं, बल्कि उनके परिवार के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार है। आर्थिक सशक्तिकरण की यह कड़ी यहीं नहीं रुकती, चमेली को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना का भी निरंतर लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता को नए पंख मिले हैं।

कबीरधाम में 'दीदियों' ने संभाली स्टीयरिंग, उपमुख्यमंत्री शर्मा बने पैसेंजर

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। कबीरधाम जिले में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अभिनव और प्रेरणादायक पहल सामने आई है, जहां अब तक पुरुष प्रधान माने जाने वाले परिवहन व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी का नया अध्याय शुरू हुआ है। इस अवसर पर स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने जब स्टीयरिंग संभाली तो उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी उनके पैसेंजर बन गए। पहले परिवहन व्यवसाय केवल पुरूष प्रधान कार्य माना जाता था, जिस मिथक को तोड़ अब समूह की महिलाएं स्टेयरिंग थामकर आजीविका का सशक्त साधन तैयार करने के साथ ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को भी नई गति देने जा रही हैं।

सरस मेले के शुभारंभ के अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जिले की 10 महिला समूहों को 'आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस' योजना के तहत सीएलएफ मैजिक वाहन वितरित किए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इन वाहनों का वितरण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्येक वाहन की लागत लगभग 7.50 लाख रुपये है, जिसमें से 5 लाख रुपये केंद्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिए गए हैं। शेष राशि का प्रबंधन संबंधित समूहों द्वारा किया गया है, जिससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होगी।

उन्होंने कहा कि अब स्व सहायता समूह की महिलाएं अपने क्षेत्रों में यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराकर आय का स्रोत विकसित करेंगी। विशेष रूप से दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में यह पहल आमजन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी, जहां अब तक परिवहन की कमी एक बड़ी समस्या रही है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि यह पहल केवल शुरुआत है। यदि महिलाएं इस अवसर का पूरी लगन और समर्पण से उपयोग करें, तो वे 'लखपति दीदी' बनने के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकती हैं। यह योजना महिलाओं की आय में वृद्धि के साथ-साथ उन्हें आत्मसम्मान और समाज में नई पहचान दिलाने का माध्यम बनेगी।

वाहन संचालन के लिए महिलाओं को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेनिंग दी गई है। यह वाहन 10 अलग अलग संकुल के महिला समूहों 10 विभिन्न ग्रामीण रूट पर संचालन हेतु प्रदान किया गया है। इस पहल के तहत महिला समूह की सदस्य अब टाटा मैजिक वाहन संचालित कर परिवहन व्यवसाय से जुड़ेंगी। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर उनकी भूमिका को भी सशक्त करेगा। योजना के तहत ये महिलाएं जिले के वनांचल एवं मैदानी क्षेत्रों में, जहां आवागमन के साधन सीमित हैं, वहां यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करेंगी। इससे न केवल दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में परिवहन सुविधा सुलभ होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

डेयरी योजना बदल रही है धनमती की तकदीर

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। गरियाबंद जिले देवभोग विकासखंड के ग्राम कुम्हड़ाईखुर्द में पशुधन विभाग द्वारा संचालित डेयरी विकास योजनाओं का लाभ अब ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से दिखाई देने लगा है। देवभोग विकासखंड के ग्राम कुम्हड़ाईखुर्द की लाभार्थी धनमती बिसी ने डेयरी योजना के माध्यम से आत्मनिर्भरता की पहल पर उल्लेखनीय कदम बढ़ाया है। उन्हें पशुपालन विभाग योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ, जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। यह सहायता उनके लिए आर्थिक सशक्तिकरण का नया आधार साबित हो रही है।धनमती बिसी अपने पति महेश बिसी के साथ मिलकर डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ मिलने से उन्होंने अपने डेयरी यूनिट का और विस्तार किया है। जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है और परिवार की आय में भी स्थायी बढ़ोत्तरी हुई है। पशुधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना और डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाना है। धनमती का कहना है कि अब वे न केवल परिवार की जरूरतें आसानी से पूरी कर पा रही हैं, बल्कि आगे चलकर और अधिक पशु पालन कर अपने कारोबार को और बड़ा करने की योजना भी बना रही हैं।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक / प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा विप्र एक्सप्रे प्रेस सीपत रोड सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय वार्ड 14 हल्दीबाड़ी एमसीबी छत्तीसगढ़ से प्रकाशित,संपादक संदीप द्विवेदी आर .एन .आई नं . सी टी एच आई एन /25/ए 1478 फोन नं .7974467831,9589645803, mediaauditor1@gmail .com पीआइबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार , सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा